हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 01 | अंक - 331 | बेमेतरा, शुक्रवार 18 जुलाई 2025 | रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित | कुल पेज - 8 | मूल्य - 5 रूपये

संक्षिप्त समाचार

गेंद ढूंढने गए शख्स को मिला कंकाल, नोकिया फोन से खुला 10 साल पुराना राज

हैदराबाद। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में एक खाली पड़े घर में 10 साल से पड़े एक कंकाल का रहस्य पुलिस ने सुलझा लिया है। सोमवार को संयोग से मिले इस कंकाल की पहचान अमीर खान नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जिसकी मौत लगभग एक दशक पहले हो गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा एक पुराने नोकिया मोबाइल फोन, बंद हो चुके नोटों और मृतक के भाई द्वारा की गई पहचान से हुआ। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को एक गेंद ढूंढने के दौरान एक व्यक्ति को इस खाली घर के किचन से यह कंकाल मिला था। जांच के दौरान पुलिस को कंकाल के पास से एक पुराना नोकिया मोबाइल फोन और तकिये के नीचे से चलन से बाहर हो चुके पुराने नोट मिले। सहायक पुलिस आयुक्त किशन कुमार ने बताया कि फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी।

विदेशों पर निर्भर न होकर भारत को अपनी तकनीक पर देना होगा ध्यान

नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने हाल के संघर्षों में ड्रोन की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि ये छोटे-छोटे हथियार जंग में पासा पलट सकते हैं। मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में जनरल चौहान ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया है कि हमारे भूभाग और हमारी जरूरतों के लिए निर्मित स्वदेशी मानवरहित हवाई प्रणालियां और सी-यूएएस क्यों महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिना हथियार वाले ड्रोन और लॉइटर मुनिशन का इस्तेमाल किया, मगर भारतीय सेना ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया। जनरल चौहान ने यह भी चेतावनी दी कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता हमारी ताकत को कमजोर कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज की जंग को कल की तकनीक से नहीं जीता जा सकता। ड्रोन और नई तकनीक अब युद्ध के मैदान में सबसे अहम हथियार बन चुके हैं।

झारखंड के बोकारो में एनकाउंटर, 25 लाख के इनामी समेत दो नक्सली ढेर

बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में सुबह से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यह मुठभेड़ जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के धनिया के आसपास के जंगलों में लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ के बीच चल रही है, जिसमें दो नक्सलियों की मौत हो गई, जबकि सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ के बीच सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने जवाब दिया।

डी.ए.पी. खाद की कमी को लेकर कांग्रेस विधायकों का जमकर हंगामा

आप लोग मेरे आग्रह की धज्जियां उड़ा रहे-विधानसभा अध्यक्ष

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा के मानसून सत्र के आज चौथे दिन विपक्ष ने पूरे प्रदेश में डीएपी खाद की कमी होने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। चर्चा के दौरान विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच खूब आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। मामला ऐसा गरमाया कि सारे विपक्षी विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते गर्भ गृह में आ गए और परंपरानुसार स्वमेव निलंबित हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित विपक्षी विधायकों को दो से तीन बार सदन से बाहर चले जाने कहा, लेकिन वे नहीं गए और गर्भ गृह में ही धरना देते हुए नारेबाजी करने लगे। कड़ी नाराजगी जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि आप लोग असंसदीय व्यवहार करते हुए 25 साल पुरानी परंपरा को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। मेरे दो बार, तीन बार के आग्रह की आप लोग धज्जियां उड़ाते रहे। इसके साथ ही अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल का सवाल था कि प्रदेश में डीएपी खाद की कितनी मांग (टारगेट) रहती है और कितनी आपूर्ति (सप्लाई) हुई है? क्या डीएपी खाद की कमी हुई है? यदि हाँ तो सरकार किसानों को डीएपी खाद किस कारण से उपलब्ध नहीं करा पा रही है? कृषि मंत्री रामविचार नेताम की ओर से जवाब आया कि खरीफ 2025 में प्रदेश के लिए भारत सरकार द्वारा डीएपी 3 लाख

10 हजार मेट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह अप्रैल से जून 2025 तक 2 लाख 19 हजार 100 मेट्रिक टन का सप्लाई प्लान भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय व्दारा जारी किया गया गया है। इसके विरुद्ध 30 जून 2025 तक 1 लाख 8 हजार 155 मेट्रिक टन की आपूर्ति हुई है। पूर्व मौसम (रबी 2024-25) का बचत स्कंध 40 हजार 746 मेट्रिक टन मिलाकर कुल 1 लाख 48 हजार 900 मेट्रिक टन का भंडारण हुआ है। वर्तमान खरीफ मौसम में 30 जून 2025 तक जारी सप्लाई प्लान के विरुद्ध कम आपूर्ति परिलक्षित हो रही है। इस प्ररिप्रेक्ष्य में कृषकों हेतु वैकल्पिक फॉस्फेटिक उर्वरकों का भंडारण कराया जा रहा है तथा इनके उपयोग हेतु कृषकों के मध्य प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उमेश पटेल ने कहा- 3 लाख 10 हजार मेट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित था, 1 लाख 48 हजार 900 मेट्रिक टन का भंडारण हुआ। इस तरह लक्ष्य के विपरीत आधे से भी कम भंडारण हो पाया। शेष की पूर्ति करने के लिए क्या प्लान है? कृषि मंत्री ने कहा- आपूर्ति हेतु विभागीय एवं मुख्यमंत्री स्तर पर सतत् भारत सरकार के संपर्क में हैं। डीएपी खाद की कमी की स्थित में दूसरा डीएपी नैनो विकल्प के रूप में आ गया है। 20 जुलाई तक 18 हजार मेट्रिक टन की आपूर्ति हो जानी है। कुल 14 रैक प्राप्त होगा। पटेल ने पूछा- आधे से भी कम खाद की बात सामने आई है।

विधायक कॉलोनी में बने क्वींस क्लब पर 1 करोड़ 12 लाख की वसूली बाकी,विधानसभा में कांग्रेस विधायक संदीप साहू के सवाल पर आया जवाब

रायपुर। राजधानी रायपुर के विधायक कॉलोनी में बने क्वींस क्लब के संचालन का जिम्मा जिस व्यक्ति को सौंपा गया था उससे 1 करोड़ 12 लाख वसूल किया जाना बाकी है। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक संदीप साहू व्दारा पूछे गए सवाल पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी का लिखित में यह जवाब आया। कांग्रेस विधायक संदीप साहू का लिखित में सवाल था कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्दारा राजधानी रायपुर के विधायक कॉलोनी में स्थित क्वींस क्लब को सर्वप्रथम संचालन हेतु किस संस्था को कब, किन शर्तों व अनुबंधों के आधार पर हस्तांतरित किया गया? शर्तों एवं अनुबंध के उल्लंघन में कब-कब, क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं? छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई? क्लब संचालक से कितनी राशि की वसूली शेष है।

डोनाल्ड ट्रंप ने तुड़वा दी मुस्लिम देशों की एकता

ईरान के बाद तबाही पर अकेला रोता रहा सीरिया

नई दिल्ली। ईरान पर मिसाइलों की बरसात करने के बाद अब एक और इस्लामिक देश इजरायल का अगला निशाना बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिम एशिया का देश सीरिया इस वक्त इजरायल के अटैक का शिकार हो रहा है। आलम ये है कि उसकी राजधानी तक पर ताबड़तोड़ हमले किए गए और रक्षा मंत्रालय को भी अपने हमलों से दहला दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजरायल की तरफ से गाजा से लेकर ईरान और अब सीरिया तक पर हमला किया जा रहा है तो इस्लामिक देशों ने चुप्पी क्यों साध रखी है। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि जब इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़

मिसाइलें दागी जा रही थी तो कुछ मुस्लिम देशों के बड़े बड़े नेता ट्रंप के साथ लंच करते नजर आए। जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि क्या मुस्लिम देशों की एकता टूट चुकी है। मुस्लिम देश अब एक दूसरे का साथ देने या मुसीबत में हाथ थामने से कतराती नजर आ रही है।

तलाक मंजूर

पत्नी ने पति पर लगाया नपुंसकता का आरोप,कोर्ट ने कहा-बिना सबूत इल्जाम लगाना है मानसिक क्रूरता

बिलासपुर। तलाक के एक मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी चिकित्सकीय प्रमाण के पति पर नपुंसकता जैसे गंभीर आरोप मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह तलाक का वैध आधार है। बता दें, कि पति ने जांजगीर-चांपा के फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पति को राहत देते हुए फैमिली कोर्ट के निर्णय को गंभीर त्रुटिपूर्ण माना और रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पति ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आरोपों को सिद्ध किया है। ऐसे में विवाह को बनाए रखना न्याय और विधि के अनुरूप नहीं होगा। जांजगीर-चांपा जिले में रहने वाले व्यक्ति की शादी 2 जून 2013 को बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में रहने वाली महिला के साथ हुई थी। पति शिक्षाकर्मी के रूप में बैकुंठपुर की चरचा कॉलरी में पदस्थ था, जबकि पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। विवाह के कुछ समय बाद पत्नी पति पर नौकरी छोड़ने या तबादला कराने का दबाव

बनाती रही। 2017 से दोनों पूरी तरह अलग रह रहे थे। सात साल बाद पति ने वर्ष 2022 में फैमिली कोर्ट में तलाक की मांग करते हुए आवेदन लगाया। सुनवाई के दौरान पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि वह यौन संबंध बनाने में असमर्थ है, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उसके पास इस दावे का कोई मेडिकल प्रमाण नहीं है। वहीं, पति ने बताया कि पत्नी ने उस पर पड़ोस की महिला से अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाया। पति पत्नी की बीच अनबन को लेकर सामाजिक बैठक में भी महिला सुलह कराने की कोशिश कर रहे अपने जीजा के साथ झगड़ा कर लिया था। साथ ही पत्नी ने पति पर पड़ोसी महिला के साथ अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि यह भी गंभीर क्रूरता की श्रेणी में आता है। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि किसी व्यक्ति पर बिना सबूत के नपुंसकता का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। यह आरोप न केवल मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि इसका पति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है

राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वार

क्या भाजपा की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका चुनाव आयोग

नई दिल्ली/ एजेंसी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की 'चुनावी चोरी शाखा' बन गया है। वहीं, चुनाव आयोग हमेशा से कहता रहा है कि 22 साल बाद हो रहे इस पुनरीक्षण से मतदाता सूची से अपात्र लोगों और डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाया जाएगा और कानून के अनुसार मतदान के पात्र लोगों को भी शामिल किया जाएगा। राहुल

गांधी ने एक्स पर एक वीडियो साक्षा करते हुए लिखा कि बिहार में चुनाव आयोग के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ़ चोरी, नाम पर्दाफाश करने वाले पर होगी निर्वाचन आयोग अब भी निर्वाचन आयोग है या पूरी तरह भाजपा की निर्वाचन चोरी शाखा बन चुका है? वहीं, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि नागरिकता प्रमाणित करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं है तथा विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर राष्ट्रीय नागरिक पंजी शुरू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि अब आयोग अपने ही तर्कों में फंस गया है और 'मुद्दा भटकाओ योजना' के तहत नेपाल, म्यांमा और बांग्लादेश के लोगों के बिहार में होने की कहानी गढ़ रहा है। कुमार ने कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' में संवाददाताओं से कहा, ''यदि 2003 की पुनरीक्षण की प्रक्रिया गलत थी, तो उसके बाद के सभी चुनाव गलत हैं...

चलती बस में दिया बच्चे को जन्म, फिर कपड़े में लपेटकर खिड़की से फेंका बाहर

परभणी। महाराष्ट्र के परभणी में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहाँ एक 19 वर्षीय महिला ने चलती बस के स्लीपर कोच में एक बच्चे को जन्म दिया और फिर अपने पति के साथ मिलकर नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी जोड़े को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे पाथरी-सेलु रोड पर घटी। संत प्रयाग ट्रैवल्स की एक स्लीपर बस में रितिका ढेरे नामक महिला अपने पति होने का दावा करने वाले अल्ताफ शेख के साथ पुणे की ओर जा रही थी।

नाटो प्रमुख के बयान पर भी बोला विदेश मंत्रालय

निमिषा प्रिया की मदद के लिए सरकार कर रही सभी प्रयास....

नई दिल्ली/ एजेंसी

यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया केस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार निमिषा प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया, 'हमने कानूनी मदद उपलब्ध कराई है और उनके परिवार की सहायता के लिए एक वकील भी नियुक्त किया है। हम स्थानीय अधिकारियों और उनके परिवार के संपर्क में हैं ताकि इस मामले का कोई समाधान निकल सके। उन्होंने आगे कहा कि बीते कुछ दिनों में यह कोशिश की गई

है कि पीड़ित परिवार को ज्यादा समय मिले ताकि वे दूसरी पार्टी के साथ कोई आपसी सहमति बना सकें। भारत सरकार इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और आगे भी हर संभव मदद करती रहेगी। इसके अलावा सरकार इस विषय में कुछ दोस्त देशों से भी संपर्क में है। वहीं नाटो महासचिव मार्क रुटे की उस टिप्पणी पर भी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं, उन्हें सेकंडरी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हमने इस विषय पर आई खबरें देखी हैं और सभी प्रगति पर करीब से नजर रख रहे हैं। मैं साफकर दूं कि भारत के लोगों की ऊर्जा जरूरतें पूरी करना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस दिशा में हम बाजार में उपलब्ध विकल्पों और वैश्विक हालात को देखते हुए निर्णय लेते हैं।

छत्तीसगढ़ के सात शहरों ने नेशनल लेवल पर बिखेरी स्वच्छता की चमक

एसएसएल में तीन शहरों ने बनाई जगह,मिला अवॉर्ड....

- छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय मंच पर बिखेरी स्वच्छता की चमक, 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में बिल्हा देश का सबसे स्वच्छ शहर

रायपुर। संवाददाता

केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सात शहरों ने अपनी स्वच्छता की चमक बिखेरी है। बिल्हा नगर पंचायत 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में अब देश का सबसे साफ-सुथरा शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। तीन लाख से दस लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को पूरे देश में दूसरा और 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में इन तीनों नगरीय निकायों के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के कुल सात नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव, संबंधित निकायों के महापौर, अध्यक्षों और अधिकारियों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और केन्द्रीय

आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर और रायपुर ने भी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार शामिल नई श्रेणी 'स्वच्छता सुपर लीग' (एसएसएल) में अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर ने जगह बनाई है। यह सम्मान उन शहरों को दिया गया, जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में रहे हैं और वर्तमान वर्ष में शीर्ष 20 शहरों में शामिल हैं। अंबिकापुर ने 50 हजार से तीन लाख जनसंख्या श्रेणी में तथा पाटन और विश्रामपुर ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में एसएसएल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इनके अतिरिक्त, राजधानी रायपुर को छत्तीसगढ़ का 'प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर' का पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने इन शहरों में स्वच्छता के प्रति नागरिकों, स्थानीय निकायों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पुरस्कार राज्य के अन्य शहरों को भी अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने भी आज पुरस्कृत नगरीय निकायों को बधाई दी और कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए केवल एक सम्मान ही नहीं।

यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का क्षण: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने इन शहरों में स्वच्छता के प्रति नागरिकों, स्थानीय निकायों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पुरस्कार राज्य के अन्य शहरों को भी अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने भी आज पुरस्कृत नगरीय निकायों को बधाई दी और कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए केवल एक सम्मान ही नहीं, बल्कि स्वच्छता के प्रति निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। आने वाले समय में अन्य नगरीय निकायों को भी स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होंगे।

डीए, पेंशन सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन

बीजापुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर बीजापुर जिले सहित पूरे प्रदेश में रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन कर प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। फेडरेशन के जिला सचिव कैलाश रामटेके ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आंदोलन फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष कमल वर्मा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के समस्त विकासखंडों में एक साथ आयोजित किया गया। बीजापुर में यह ज्ञापन एसडीएम जागेश्वर कौशल को सौंपा गया। प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं -1. केंद्र सरकार के अनुरूप 2त्न महंगाई भत्ता एवं वर्ष 2019 से लंबित डीए की एरियर्स राशि का भुगतान। 2. पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। 3. चार स्तरीय पदोन्नति समयमान वेतनमान लागू किया जाए।4. वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए।5. कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू हो।6. अनुकंपा नियुक्ति में 10त्न सीमा समाप्त हो।7. अर्जित अवकाश का 300 दिवस तक नगदीकरण किया जाए।8. पूर्ण पेंशन के लिए निर्धारित नीति बनाई जाए।9. सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाए।10. समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई, तो आगामी 22 अगस्त 2025 को सामूहिक अवकाश लेकर सभी विकासखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

भोपालपटनम में भी सौंपा गया ज्ञापन -भोपालपटनम विकासखंड में ब्लॉक अध्यक्ष कमल कोर्राम के नेतृत्व में रैली निकाली गई और ज्ञापन तहसीलदार के रीडर को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में लोकेश रेड्डी (कोषाध्यक्ष), रेश्मा गोड्डे (सह सचिव), सोनाधर मांझी, कश्मीर एक्का, मोहन अवलम (वन कर्मचारी संघ), शेख फारुख (स्वास्थ्य कर्मचारी संघ), महेश देवांगन (वाहन चालक संघ), इलमिडी संतोष (लिपिक संघ), संदीप राज पामभोई, शेख आसम, सुशीला लांबाड़ी (शिक्षक संघ), ए. सुधाकर (पेंशनर संघ), शंकर कावटी, मोहनलाल मंडावी, कोरम नारद, मद्दी नागैया सहित अन्य कर्मचारीगण प्रमुख नाम शामिल रहे।

उदयपुर फाइल्स पर लगी रोक हटाने की मांग, विहिप-बजरंग दल ने सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

जगदलपुर/बस्तर /मूक पत्रिका

राजस्थान के उदयपुर में वर्ष 2022 में हुई कन्हैयालाल की जघन्य हत्या पर आधारित फिल्म ÷उदयपुर फाइल्स÷ की रिलीज़ पर न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बस्तर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताया गया खतरे में फिल्म को बताया सच्ची घटना पर आधारित फिल्म निर्माताओं को सुरक्षा देने की भी रखी मांग, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिला बस्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एकजुट होकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और माननीय मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ÷उदयपुर फाइल्स÷ फिल्म की रिलीज़ पर न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। बजरंग दल जिला संयोजक मुन्ना कोरी ने कहा कि यह फिल्म 2022 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। फिल्म पर लगी रोक को आतंक के विरुद्ध उठी एक सशक्त आवाज को दबाने का प्रयास करार देते हुए उन्होंने कहा, ÷जनता को सच्चाई देखने और समझने का अधिकार है।÷विहिप सेवा विभाग प्रमुख अनिल अग्रवाल ने कहा कि यदि किसी पक्ष को फिल्म की विषयवस्तु से आपत्ति है, तो उसके लिए सेंसर बोर्ड और न्यायिक प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। सीधे फिल्म पर प्रतिबंध लगाना न केवल गैरलोकतांत्रिक है, बल्कि यह संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है। संगठन ने यह भी मांग की कि फिल्म निर्माताओं को प्रशासनिक सुरक्षा और न्यायिक संरक्षण मिले ताकि वे निडर होकर सच्चाई समाज के सामने ला सकें। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रमुख पदाधिकारीयो में अनिल अग्रवाल (सेवा प्रमुख, विहिप),मुन्ना बजरंगी (जिला संयोजक, बजरंग दल),विष्णु ठाकुर (गौ संवर्धन प्रमुख),भवानी सिंह चौहान (नगर संयोजक),संजय मुखर्जी (नगर अर्चक पुरोहित),हेमराज कश्यप, पवन राजा, रोहित झा, चकरी राव, लोचन सोनी,मनीष भाटी, मुकेश पानीग्राही, जशवंत जोशी, काशी चालकी, योगेश ठाकुर आदि। संगठन ने केंद्र व न्यायपालिका से यह आग्रह किया है कि ÷उदयपुर फाइल्स÷ फिल्म की रिलीज़ को तत्काल सुनिश्चित कर राष्ट्रहित, सनातन आस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाए।

बस्तर के सांसद पहुंचे दंतेवाड़ा रेडियो स्टेशन, आरजे प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से की मुलाकात

दंतेवाड़ा /मूक पत्रिका

दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप द्वारा दंतेवाड़ा रेडियो स्टेशन में संचालित आरजे प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे युवाओं से मुलाकात कर संवाद किया गया। इस मौके पर सांसद कश्यप ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से उनके अनुभव साझा किए, उनके सवालों का जवाब दिया और रेडियो, जनसंचार तथा संवाद कला से जुड़े विभिन्न विषयों पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि, ÷बस्तर के युवाओं में रचनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता हैं और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें नए अवसरों की ओर ले जाते हैं।÷ प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने रेडियो जॉकी आरजे बनने से जुड़ी तकनीकी जानकारी, प्रस्तुति कौशल, स्क्रिप्ट लेखन और साक्षात्कार विधा जैसे विषयों में सक्रिय भागीदारी दिखाई। इसी क्रम में प्रशिक्षुओं द्वारा सांसद महेश कश्यप का एक रोचक सजीव साक्षात्कार भी लिया गया, जो सवाल-जवाब, और सीख से भरपूर रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बस्तर के युवाओं को रेडियो और जनसंचार के क्षेत्र में न केवल प्रशिक्षण देना है, बल्कि उन्हें रोजगार, आत्मविश्वास और सामाजिक नेतृत्व की दिशा में प्रेरित करना भी है। इस अवसर पर रेडियो स्टेशन की टीम, प्रशिक्षकगण और बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर सांसद ने सभी प्रशिक्षुओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और रेडियो के माध्यम से सकारात्मक समाज निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान किया।

क्षेत्र जनपद सदस्य एवं शिक्षा समिति सदस्य, वन समिति सदस्य पवन कर्मा स्कूली बच्चों से हुए रूबरू

भिंजाम, सियानार पहुंचे जनपद सदस्य पवन कर्मा

दंतेवाड़ा /मूक पत्रिका

जिले के गीदम विकासखण्ड अन्तर्गत बीते गुरुवार को सियानार स्कूल भिंजाम स्कूल पहुंचे जनपद पंचायत सदस्य पवन कर्मा। जहां पूरे संकुल का एक एक स्कूल जाकर बच्चों से रूबरू एवं बच्चों में पढ़ाई की जानकारी बच्चों की भोजन की गुणवत्ता जानकारी एवं बच्चों के साथ बैठकर चर्चा सामान्य ज्ञान जैसे विषय जैसे क्षेत्र के विधायक जी का नाम पूछा गया तो बच्चों ने बड़े प्यार से बोले चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नदलाल मुडामी जिले के कलेक्टर का भी नाम पूछा गया बच्चों ने जवाब देते हुए कहा इनका नाम हम जानते हैं कुणाल दुदावत बताया गया। इसके साथ बच्चों की पढ़ाई के बारे में और अति उत्साह वर्धन करने एवं पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को संस्कृति कार्यक्रम खेलकूद की मनोरंजन इत्यादि विषय में भी चर्चा किया गया है जिसमें उपस्थित संकुल प्रभारी गोटिया सर उपस्थित रहे ।जिन स्कूल में समस्या एवं परेशानी है उससे भी जनपद सदस्य पवन कर्म कोअवगत कराया गया है । जनपद सदस्य पवन कर्म ने कहा कि मेरे जनपद क्षेत्र में जो समस्या की जानकारी होगी उससे मुझे अवगत कारण मैं आप सभी की समस्या को लेकर माननीय कलेक्टर सर जी को लिखित अवगत कर समस्या का समाधान करने के लिए निवेदन करूंगा ऐसा आश्वाशन जनपद सदस्य पवन कर्मा के द्वारा दिया गया शिक्षकों को निवेदन भी किया गया की पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को सामान्य ज्ञान, खेलकूद,स्थानीय खेल का भी ज्ञान भी दिया जाता रहे।

बेमेतरा तहसील में नए तहसीलदार का कोटवार संघ ने किया स्वागत

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बेमेतरा दाढ़ी तहसील में हाल ही में पदस्थ किए गए नए तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा का बीते गुरुवार को तहसील कार्यालय परिसर में कोटवार संघ द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर कोटवार संघ के सदस्यों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर सौजन्य भेंट दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में यह स्वागत समारोह सम्पन्न हुआ। कोटवार संघ ने आशा जताई कि नए तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और समन्वय बढ़ेगा तथा ग्रामीण स्तर पर राजस्व व्यवस्था और मजबूत होगी। स्वागत कार्यक्रम में सिया सिंह चौहान, दौलत मानिकपुरी, तामेश्वर मानिकपूरी, सतानन्द चौहान, रामावतार सिंह चौहान, हीरा दास मानिकपुरी, ईश्वर दास, संतराम रजक, तारण दास, पंचराम एवं केशव दास सहित अन्य कोटवार साथी उपस्थित रहे।

व्यापम द्वारा आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 27 जुलाई को जिले के 04 हजार 300 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

केन्द्र में प्रवेश के पूर्व हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से होगी जांच

मुंगेली/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) रायपुर द्वारा आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा 27 जुलाई को प्रातः 10 से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में जिले के 04 हजार 343 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। व्यापम द्वारा आगामी परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सफलतापूर्ण आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पूर्व सभी परीक्षार्थियों की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम 02 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचना आवश्यक होगा, ताकि शारीरिक जांच और प्रवेश पत्र सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधे बाँह के कपड़े तथा चप्पल पहनकर परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण, घड़ी, पर्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि साथ लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व एवं अंतिम आधे घंटे में कक्ष से बाहर जाना वर्जित रहेगा। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य है।

कांकेर की बेटियों का दमदार प्रदर्शन वूमेंस लीग में जूनियर वर्ग की उपविजेता बनी टीम

■ वेटलिफ्टिंग में राज्य स्तरीय अस्मिता खेलों इंडिया

कांकेर /मूक पत्रिका

जिले की बेटियों ने एक बार फिर प्रदेश स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। महुदा ग्राम विकासखंड पाटन में आयोजित राज्य स्तरीय अस्मिता खेलों इंडिया वूमेंस लीग प्रतियोगिता में कांकेर की जूनियर वेटलिफ्टिंग टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जूनियर वर्ग में उपविजेता का खिताब अपने नाम किया।प्रतियोगिता में कांकेर जिले से विभिन्न वजन वर्गों में कुल 13 बालिकाएं चयनित हुई थीं। सभी प्रतिभागी नरहरपुर विकासखंड के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अभनपुर की छात्राएं हैं, जो जिले के लिए गर्व का विषय है। 44 किग्रा (यूथ वर्ग) किरण सरोज 44 किग्रा (यूथ + जूनियर वर्ग) - अंकिता विश्वकर्मा, शांता यादव, वसुंधरा नेताम, 48 किग्रा (सीनियर वर्ग) - पेनालिका यादव, 53 किग्रा (यूथ जूनियर वर्ग) प्रीति मरकाम, लता नेताम, 58 किग्रा (यूथ वर्ग) बरखा चक्रधारी 58 किग्रा (यूथ + जूनियर वर्ग) - चंचल नेताम 63 किग्रा (यूथ जूनियर वर्ग) ललिता चक्रधारी 69 किग्रा (यूथ + जूनियर वर्ग) ज्योति नेताम (रजत पदक) +77 किग्रा (यूथ + जूनियर वर्ग) - वंदना भास्कर (कांस्य पदक) इस प्रतियोगिता में ज्योति नेताम ने 69 किग्रा (यूथ वर्ग) में रजत पदक और वंदना भास्कर ने +77 किग्रा (यूथ वर्ग) में कांस्य पदक जीतकर व्यक्तिगत श्रेणियों में भी कांकेर जिले को गौरवान्वित किया। इस सफल टीम का संचालन टीम मैनेजर श्रीमती मिताली सुमीत घोष एवं कोच सुश्री माधुरी साहू के मार्गदर्शन में हुआ। टीम को निरंतर सहयोग देने वाली संरक्षक श्रीमती सत्या भास्कर, विद्यालय प्राचार्य रामप्रसाद नेताम, समस्त शिक्षकगण और कांकेर जिला वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष टेकेश्वर सिन्हा सहित सभी पदाधिकारियों ने बालिकाओं को उनकी सफलता पर शुभकामनाएं दीं।

गोदावरी इस्पात के खिलाफशिवसेना का जनजागरण अभियान जल्द शुरू, ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकों का दौर जारी

कांकेर /मूक पत्रिका

भानुप्रतापपुर क्षेत्र में गोदावरी इस्पात कंपनी के खिलाफ जन असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय पर्यावरण, जंगलों की अवैध कटाई, कच्चे लौह अयस्क का अंधाधुंध दोहन, और स्थानीय युवाओं को दरकिनार कर भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोपों के बीच शिवसेना ने इस शोषण के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि गोदावरी इस्पात कंपनी क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर शासन कर रही है÷, जहां जनता की सहमति के बिना संसाधनों का दोहन किया जा रहा है और ग्रामीणों को उनका हक एवं अधिकार नहीं मिल रहा।शिवसेना द्वारा भानुप्रतापपुर के आस-पास के गांवों में गांव स्तरीय जन बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में पार्टी कार्यकर्ता ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि किस प्रकार क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को निजी कंपनी द्वारा व्यावसायिक हितों के लिए अनियंत्रित रूप से उपयोग किया जा रहा है। बैठकों में ग्रामीणों को यह भी बताया जा रहा है कि, किस तरह जंगलों की अवैध कटाई और खनिज उत्खनन से क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को दरकिनार कर बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है, और किस प्रकार यह सब क्षेत्रीय विकास की बजाय लाभ के केंद्रीकरण में बदल गया है। शिवसेना के अनुसार, यदि यह शोषण यूँ ही चलता रहा तो शीघ्र ही जनजागरण अभियान प्रारंभ कर क्षेत्र की जनता को संगठित किया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य कंपनी के एकाधिकार और मनमानी कार्यप्रणाली को रोकना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना और क्षेत्र के हक की लड़ाई को मजबूत करना है। इस सिलसिले में भानुप्रतापपुर में एक विशेष बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें शिवसेना पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आगामी रणनीति पर चर्चा की। शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन मौन है और कंपनी को संरक्षण मिल रहा है। इस संबंध में उन्होंने शासन से मांग की है कि क्षेत्र में अवैध खनन और वनों की कटाई की जांच कराई जाए, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए और क्षेत्रीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।

मासिक धर्म के बारे में खुली बातचीत कर इसे सामान्य रूप से स्वीकार करने की जागरूकता की आवश्यकता जताई गई - डॉ मनीष बंजारा

महिला जागृति मंडल के द्वारा माहवारी संगोष्ठी का आयोजन प्रेस क्लब मुंगेली में सम्पन्न

संगोष्ठी में, मासिक धर्म चक्र, स्वच्छता, और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जानकारी दी गई

डॉ मनीष बंजारा और डॉ प्रियंका जांगड़े ने माहवारी संगोष्ठी में अहम जानकारी दी

मुंगेली/मूक पत्रिका

जागृति महिला जन कल्याण समिति मुंगेली द्वारा माहवारी की जागरूकता के लिए प्रेस क्लब मुंगेली में माहवारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें माहवारी को ''प्राकृतिक देन है कोई अभिशॉप नही'' का संदेश को जागरूकता के साथ लोगो तक पहुचाने का अनुकरणीय प्रयास किया गया। कार्यक्रम का अतिथि डां. मनीष बंजारा एवं डां. प्रियंका जांगड़े रहे।

जागृति महिला जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सावित्री सोनी एवं सदस्यों ने डां. मनीष बंजारा व डां. प्रियंका जांगड़े का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। समिति के अध्यक्ष सावित्री सोनी ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं की स्थिति पूरे क्षेत्र में आज उन्नतशील है और आज देश की रक्षा में आज महिलाएं अपने योगदान की पताका फहरा रही है। वहीं दूसरी तरफ माहवारी के विषय में आज भी महिलाओं की स्थिति चिंतनीय है उन्हें जागरूक करने आवश्यकता आज भी बनी हुई है इस लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्होंने संगोष्ठी में उपस्थित छात्रों व महिलाओं से आग्रह किया कि वे इस विषय में अपनी शंका समाधान करने के लिए खुलकर चर्चा करे और प्रश्न पूछे। इसके पश्चात कार्यक्रम के उदबोधन के लिए डां. मनीष बंजारा को आमंत्रित किया। डां. मनीष बंजारा ने जागृति महिला जन कल्याण समिति, महिला बाल विकास की उपस्थित प्रतिनिधि, चेतना वरिष्ठ महिला संघ के सदस्य एवं मितानीनयों को सादर अभिवादन करते हुए कहा कि आज हम सभी लोग माहवारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए है इस विषय को लेकर लोग उतना जागरूक नहीं है जिससे माहवारी को लेकर अनेक भ्रांतियां रही है और शर्म व छूआछूत के विषय में फसा माहवारी जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया होने के बावजूद भी अभिशप्त ही रहा है, आज के इस आधुनिक युग में महिलाओं को माहवारी के विषय में जागरूक होकर निसंकोच अपनाना होगा और यह साबित करना होगो माहवारी एक प्राकृतिक देन है इसके लिए आपको और हमको जागरूकता के लिए बहुत कार्य करना होगा, समाज में जागरूकता लाना होगा और इस माहवारी को नयी पीढ़ी की युवति व बच्चियों को पूर्ण जानकारी देकर जागरूक करना है कि यह शर्म का विषय नही रहे छिपाने का विषय नहीं रहे बल्कि इसे स्वीकार का स्वच्छ रहने की जरूरत है।

संगोष्ठी में उपस्थित महिला एवं छात्राओं ने भी प्रश्न पूछे - संगोष्ठी में प्रश्न भी पूछे गये जिसमें मासिक धर्म से होने वाले परेशानियों से बचाव के प्रश्न थे सफेद पानी जाना और रक्त के कलर को लेकर था और पीसीओडी के सवाल थे जिसमें डॉक्टर ने बताया कि बिना बदबूदार सफेद पानी जाना स्वभाविक है। रक्त के कलर हल्के गुलाबी और गाढ़ा लाल के प्रश्न में उन्हें बताया गया कि यदि बदबूदार न हो तो चिंता करने की आवश्कता नही है। डां प्रियंका जांगड़े ने बताया कि पीसीओडी एक हॉर्मोनल का असंतुलन है जिसके कारण अण्डाशय में छोटी-छोटी गाठें बन जाती है ये गांठें आमतौर पर अपरिपक्व अण्डे होते है जो अण्डाशय में जमा हो जाते है जिससे मासिक धर्म अनियमित हो जाता है और चेहरे पर बाल मुहासे के लक्षण दिखायी देते है जो बाझपन जैसे गंभीर समस्या की ओर इंगित करता है। उल्लेखनीय है कि उपस्थित एक छात्रा ने बताया कि उन्हें अपने पिता से माहवारी/पीरियड की जानकारी मिलने के कारण माहवारी शुरू होने से कोई परेशानी नहीं हुई। इस पर उस पिता के मार्गदर्शन के लिए उन्हे धन्यवाद देते हुए समाज से इसी प्रकार अपेक्षा जताई गई।

जानिए मासिक धर्म क्या है -डां मनीष बंजारा ने बताया कि पहला मासिक धर्म, जिसे मेनार्चे के नाम से भी जाना जाता है, आमतौर पर यह 9 से 15 वर्ष की आयु के मध्य आरंभ होता है, मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय की परत टूटकर योनि से रक्त और ऊतक के रूप में बाहर निकलती है. यह हर महीने होता है और गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करता है। सामान्य तौर पर इसकी औसत आयु लगभग 12 वर्ष होती है। लेकिन खान-पान, रहन-सहन एवं वातावरण का इस पर भी असर पड़ता है। जिससे यह आगे पीछे भी होता है और कहीं- कहीं 8 वर्ष से यह आरंभ होता है। कुछ मामले में यह 16 वर्ष की उम्र तक भी नहीं आता है, मासिक धर्म 45 से 50 वर्षो के बाद स्वयंमेव बंद हो जाता है। हालांकि अपवादित घटना शुरू व बंद दोनो स्थितियों में होती है। मासिक धर्म के दौरान कुछ महिलाओं को ऐंठन, थकान, सिरदर्द, बुखार या मूड स्विंग का अनुभव हो सकता है।

कृषक उन्नति योजनांतर्गत लाभ हेतु 31 अक्टूबर तक पंजीयन अनिवार्य

मुंगेली/मूक पत्रिका

शासन द्वारा कृषकों को पर्याप्त निवेश सहायता एवं लागत राहत देने के उद्देश्य से ''कृषक उन्नति योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 'एकीकृत किसान पोर्टल' में 31 अक्टूबर तक पंजीयन, फसल सुधार, कैरी फारवर्ड आदि कार्य कराना अनिवार्य है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत कृषकों को खरीफ मौसम की प्रमुख फसलों जैसे दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास आदि के लिए 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही, समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराने पर 11 हजार रूपए की प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या सेवा सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

कांकेर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आव्हान पर बीते गुरुवार को कांकेर में जिला संयोजक प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस रैली में जिलेभर के विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए और फेडरेशन ने राज्य शासन को चेताया कि यदि मांगों का समय पर समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

मांगों की मुख्य रूपरेखा -जिला संयोजक प्रमोद तिवारी ने बताया कि फेडरेशन की प्रमुख मांगें केंद्र सरकार की 'मोदी गारंटी' के अनुरूप हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

1. महंगाई भत्ताः प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान 2त्न महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए।

2. एरियर्स का समायोजनः जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।

3. पिंगुआ समिति की रिपोर्टः वेतन विसंगति संबंधी गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

4. समयमान वेतनमानः सेवा अवधि के अनुसार 8, 16, 24 एवं 30 वर्षों पर चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान लागू किया जाए।

5. सेवानिवृत्ति आयुः सभी विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जाए।

6. नियमितीकरणः संविदा, कार्यभारित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर नियमित पदस्थापना दी जाए।

7. कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाः अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए।

8. अनुकंपा नियुक्तिः अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्थायी आदेश जारी कर सीधी भर्ती में 10त्न सीमा हटाई जाए।

9. अर्जित अवकाश का नगदीकरणः मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 300 दिवस अर्जित अवकाश का नगदीकरण लागू किया जाए।

10. पुरानी पेंशनः एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू करते हुए सेवा गणना कटौती तिथि से की जाए।

11. तृतीय समयमान वेतनमानः सहायक शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति आदेश जारी किए जाएं।फेडरेशन ने चेताया कि यदि दिनांक 16 जुलाई 2025 तक इन मांगों का निराकरण नहीं किया गया, तो आंदोलन का प्रथम चरण 16 जुलाई को ज्ञापन सौंपकर पूर्ण किया जाएगा। इसके पश्चात यदि 22 अगस्त 2025 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो 22 अगस्त को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला, विकासखंड व तहसील मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस रैली और ज्ञापन कार्यक्रम में सुरेंद्र ठाकुर, हरीश कोडोपी, देवाल सिंह नेताम, राम कुमार जैन, रामेश्वर साहू, नंद कुमार सोनलोई, सुमन शर्मा, जय सिंह सोनकर, प्रशांत रवानी, सत्यप्रकाश शर्मा, छविलाल डडसेना, सुनील कुमार साहू, रवि महंत, पियूष कौशिक, एस.पी. मंडावी, श्रवण ध्रुव समेत बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

दिशा समिति की बैठक संपन्न, सांसद बोले - केंद्र व राज्य की योजनाओं को धरातल पर उतारना सबसे बड़ी जिम्मेदारी

बीजापुर/मूक पत्रिका

बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ÷दिशा÷ की बैठक गुरुवार को बीजापुर जिला कार्यालय स्थित इन्द्रावती सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद कश्यप ने कहा कि ÷प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक बस्तर को पूरी तरह नक्सलमुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।÷ उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को आपसी समन्वय के साथ जमीनी स्तर तक पहुंचाना हम सभी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ÷विपरीत परिस्थिति और कठिन चुनौतियों के बावजूद बीजापुर जिला प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण अब प्रशासन योजनाओं को सुदूर अंचलों तक सफलता पूर्वक पहुंचा पा रहा है।÷ सांसद ने कहा कि कभी माओवाद के नाम से पहचान रखने वाला बीजापुर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और पर्यटन के लिए जाना जाने लगा है। माओवाद के समूल खात्मे के बाद क्षेत्र में विकास और तीव्र गति से होगा। इसके लिए शासन-प्रशासन को और भी समर्पण के साथ कार्य करना होगा। बैठक में कलेक्टर संबित मिश्रा ने जिले में संचालित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की जानकारी दी। विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, फसल बीमा योजना, सड़क योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, बाल विकास सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई।बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी, जनपद अध्यक्ष सोनू पोटाम, डीएफओ रंगानाथा रामाकृष्णा वाय, जिला पंचायत सीईओ हेमंत रमेश नंदनवार, एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्ना, संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर व सीएमओ उपस्थित रहे।

लायंस इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित

जांजगीर चांपा /मूक पत्रिका

लायंस इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शानदार खेल भावना का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन लायन रामप्रपन्न देवांगन उपस्थित रहे। उनके साथ लायंस क्लब अध्यक्ष लायन संतोष सोनी, क्लब सचिव लायन राजेश अग्रवाल, लायन सुरेश अग्रवाल तथा उपाध्यक्ष लायन डॉ. के. पी. राठौर भी मंच पर उपस्थित थे। इन सभी विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। अपने उद्बोधन में अतिथियों ने बच्चों को शतरंज जैसे बौद्धिक खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और बताया कि ऐसे खेल विद्यार्थियों में एकाग्रता, रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करते हैं।

श्रवण साहू चुना गया माँ भद्रकाली तहसील मानस संघ साज़ा का अध्यक्ष

संघ की वेर्चुवल बैठक मे लिया गया निर्णय

बेमेतरा/मूक पत्रिका

मां भद्रकाली जिला मानस संघ की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल मीटिंग 16 जुलाई को संपन्न हुई, जिसमें संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्यगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक में संगठनात्मक अनुशासन और मर्यादा साहित्य सामजिक क्षेत्र मे बहुत ही कम समय लोकप्रियता हासिल करने वाले श्रवण कुमार साहू को सर्वसम्मति से साजा ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया! बैठक मे प्रभारी नरेंद्र जायसवाल ने नाम प्रस्तावित किया तत्पश्चात् संरक्षक महेंद्र सिंह चौहान ने समर्थन किया तथा विधिवत जिला अध्यक्ष देवलाल सिन्हा ने श्रवण साहू के नाम अनुमोदन कर प्रस्ताव पारित किया जिस पर सर्व सम्मति से ध्वनि मत से श्रवण साहू को साज़ा तहसील का अध्यक्ष चुना गया बताना जरूरी है सनातन संस्कृति एवं आध्यात्मिक मानस उत्थान के अंतर्गत संघ की ओर से अनेक नवाचार किया जा रहा है जो जन मानस को मानस से जोड़ने का अनूठा पहल है इस अवसर पर डॉ ओंकार चंद्राकर राजकुमार ताम्रकार, माखन साहू , बिहारी यदु , उत्तम साहू महराज दिन धीवर , कल्याणी सेन, बेबी साहू, महेश साहू सनत साहू, डॉ ललित साहू , लता निषाद, भीखम देवांगन, विष्णु साहू , अदालत वर्मा, छगन साहू सहित बड़े संख्या में संघ के सलाहकार संरक्षक सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। संगठन के अध्यक्ष, प्रभारी एवं सदस्यों का आभार जताते हुए श्रवण साहू ने कहा कि इस पद को मैं सम्मान की दृष्टि से नही बल्कि एक सेवा की दृष्टि से देख पा रहा हूं, सदैव संगठन का अनुशासन में रहकर ही कार्य करूं यह प्राथमिकता रहेगी।

जिले में उर्वरक विक्रय में अनियमितता पर तीन कृषि केन्द्रों का प्राधिकर पत्र 15 दिवस के लिए निलंबित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार उर्वरकों की कालाबाजारी, तस्करी, डायवर्सन, जमाखोरी, अधिक कीमत पर विक्रय, अमानक एवं नकली उर्वरकों के व्यापार को रोकने हेतु जिले में औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।जिला स्तरीय निरीक्षण टीम द्वारा 20 जून 08 जुलाई एवं 10 जुलाई 2025 को तीन कृषि केन्द्रों मेसर्स बी.के. कृषि केन्द्र, ग्राम-बैजी, मेसर्स अर्जुन कृषि केन्द्र, ग्राम-सिंघौरी, एवं मेसर्स वैदिक कृषि केन्द्र, ग्राम-बैजी, (विकासखण्ड-बेमेतरा, जिला--बेमेतरा) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रय में अनियमितताएं पाई गईं। इस पर संबंधित कृषि केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए। फलस्वरूप उर्वरक निरीक्षक सह सहायक संचालक कृषि, बेमेतरा द्वारा तीनों केन्द्रों के उर्वरक प्राधिकर पत्र को निलंबित करने की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आधार पर मोरखंज डुडसेना, प्राधिकृत अधिकारी सह उप संचालक कृषि, जिलाङ्कबेमेतरा ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मे. बी.के. कृषि केन्द्र ग्राम बैजी, मे. अर्जुन कृषि केन्द्र ग्राम सिंघौरी, एवं मे. वैदिक कृषि केन्द्र ग्राम बैजी का उर्वरक प्राधिकर पत्र 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में उक्त केन्द्र किसी भी प्रकार से उर्वरकों का भंडारण एवं विक्रय नहीं कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

श्रम कल्याण निरीक्षक छलेश्वर साहू की सेवाएं मूल प्लेसमेंट में हुईं वापस

■ शिकायतों की जांच के उपरांत जिला कार्यालय बेमेतरा ने लौटाई सेवाएं

बेमेतरा/मूक पत्रिका

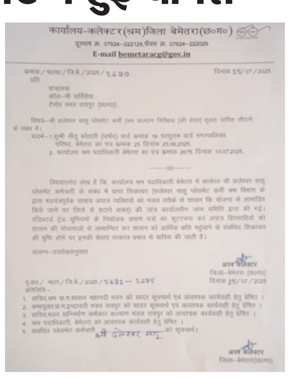
कार्यालय-कलेक्टर(श्रम)जिला बेमेतरा(छ०ग०)
E-mail bemetaracg@gov.in

कार्यालय कलेक्टर (श्रम), जिला बेमेतरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रम कल्याण निरीक्षक छलेश्वर साहू, जो कि कार्यालय श्रम पदाधिकारी बेमेतरा में प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, उनकी सेवाएं मूल प्लेसमेंट को वापस कर दी गई हैं। यह निर्णय पार्षद सुश्री नीतू कोठारी द्वारा परशुराम वार्ड, नगर पालिका परिषद बेमेतरा से संबंधित शिकायत तथा कार्यालय श्रम पदाधिकारी बेमेतरा को प्राप्त पत्रों के आधार पर लिया गया। शिकायतों में आरोप था कि निरीक्षक साहू द्वारा शासन की योजनाओं से लाभान्वित अभ्यर्थियों को गलत प्रमाण पत्र प्रदान कर आर्थिक हानि पहुँचाई जा रही है। जांच के दौरान पाया गया कि उन्होंने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के नियुक्ति प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग करते हुए पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलने दिया।

उक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर अपर कलेक्टर, जिला बेमेतरा द्वारा छलेश्वर साहू की सेवाएं तत्काल प्रभाव से मूल प्लेसमेंट को लौटाने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश की प्रतिलिपि सचिव, श्रम संचालनालय तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।

नक्सलियों को आश्रय देने वाला आरोपी गिरफ्तार, हत्या के प्रयास में निभाई थी भूमिका

कांकेर/मूक पत्रिका

जिला पुलिस को नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सलियों को आश्रय देने और उनके लिए सामग्री की आपूर्ति करने वाले आरोपी रमेश कुमार मंडावी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर भाकपा (माओवादी) संगठन के सक्रिय नक्सलियों के साथ मिलकर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में सहयोग करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी रमेश कुमार मंडावी (35 वर्ष), ग्राम कोकवार, थाना आमाबेड़ा का निवासी है। वह लंबे समय से कुंयेमारी-किसकोड़ो एरिया कमेटी के वांछित नक्सलियों, जिनमें कमांडर प्रसाद भी शामिल है, के साथ लगातार संपर्क में था। पुलिस के अनुसार, रमेश ने इन नक्सलियों को अपने घर में शरण देने, जन अदालत व शहीद सप्ताह की बैठकों के आयोजन तथा सामग्री आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. थाना आमाबेड़ा में दर्ज अपराध क्रमांक 16/2022 के अंतर्गत आरोपी पर धारा 147, 148, 149, 307 भादवि, 25, 27 आम्स एक्ट, एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धाराएं 23, 38(2), 39(2), 17, 18-1, 19 के तहत मामला दर्ज है।इस कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकआई. के. एलिसेला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण तथा डीएसपी नक्सल ऑपरेशन गिरिजाशंकर साव, डीएसपी डीआरजी अविनाश ठाकुर और डीएसपी प्रतिभा लहरे के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। आरोपी को 16 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस केस से जुड़े अन्य फरार नक्सलियों और उनके सहयोगियों की भी तलाश जारी है, और जल्द ही और गिरफ्तारियों की संभावना है। कांकेर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नक्सलियों को किसी भी प्रकार की सहायता, आश्रय या सामग्री न दें। साथ ही, नक्सल गतिविधियों में लिप्त लोग छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभलेकर मुख्यधारा में लौटें, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में पुनः स्थापित हो सकें।

धान खरीदी वर्ष 2025-26 हेतु एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1.23 लाख कृषकों का पंजीयन पूर्ण, पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया की ओर बड़ा कदम

बेमेतरा/मूक पत्रिका

आगामी धान खरीदी वर्ष 2025-26 को सुचारु, पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कृषकों का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इस योजना के तहत बेमेतरा जिले में अब तक कुल 1.23 लाख कृषकों की किसान आईडी बनाकर पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जो पारदर्शी उपार्जन प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रदेश स्तर पर एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में ई-केवाईसी आधारित पंजीयन किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक कृषक की वास्तविक पहचान सुनिश्चित हो रही है और दोहराव की संभावना समाप्त हो रही है। राज्य शासन ने इस बार कृषि विभाग, खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग के मध्य इंटर-डिपार्टमेंटल समन्वय को विशेष रूप से सुदृढ़ किया है, ताकि सभी विभाग मिलकर किसानों को समयबद्ध लाभ पहुंचा सकें। धान उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जो एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें न केवल नवीन पंजीयन की सुविधा है, बल्कि फसल रकबे में संशोधन, आधार सीडिंग और भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण भी सुनिश्चित किया गया है। खाद्य विभाग के धान खरीदी पोर्टल को सीधे एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री से एपीआई के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे पंजीकृत किसानों का डाटा रीयल टाइम में अपडेट हो रहा है। वहीं, राजस्व विभाग द्वारा संचालित भुइयाँ पोर्टल में दर्ज भूमि की जानकारी और गिरदावरी रिकॉर्ड को भी आधार नंबर से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। अब तक जिले में 85त्न भूमि रिकॉर्ड का आधार सीडिंग किया जा चुका है और शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जिले की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे शिविर लगाकर किसान पंजीयन और आईडी निर्माण का कार्य तेजी से करें। उल्लेखनीय है कि गतवर्ष कुल 1.65 लाख कृषकों का पंजीयन धान उपार्जन हेतु हुआ था, जिनकी भी आईडी इस बार एग्रीस्टैक में अपडेट की जा रही है। इस तकनीकी पहल से किसानों को न केवल योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा, बल्कि उपार्जन प्रक्रिया भी अधिक सहज और भरोसेमंद होगी 7 राज्य शासन की यह पहल डिजिटल इंडिया के तहत कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार का उदाहरण है, जिससे किसानों को सुविधा, पारदर्शिता और समयबद्ध लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।

शिवनाथ नदी में बाढ़ आपदा की मॉकड्रिल, टापू में फंसे लोगों का जीवंत रेस्क्यू, मॉकड्रिल में दिखा बाढ़ आपदा से निपटने का दम

शिवनाथ नदी में बाढ़ आपदा से निपटने मॉकड्रिल का आयोजन, कलेक्टर रणबीर शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

संभावित बाढ़ आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बीते गुरुवार सुबह 8 बजे ग्राम अमोरा (जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर) स्थित शिवनाथ नदी तट पर व्यापक स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर रणबीर शर्मा स्वयं उपस्थित रहकर संपूर्ण रेस्क्यू प्रक्रिया का अवलोकन किया और सभी तैयारियों की समीक्षा की। इस मॉकड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, आमजन को जागरूक करना और प्रशासनिक समन्वय का परीक्षण करना था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज, एडीएमअनिल बाजपेयी, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती दीप्ती वर्मा, एसडीएम श्रीमती दिव्या पोटाई, श्रीमती पिंकी मनहर, जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य, राजस्व एवं अन्य विभागों सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

रेस्क्यू ऑपरेशन का जीवंत प्रदर्शन-मॉकड्रिल के तहत बाढ़ आपदा की स्थिति का यथार्थ सिमुलेशन करते हुए एसडीआरएफ टीम ने पहले से निर्धारित योजना के अनुसार कुछ लोगों को नदी के उस पार स्थित टापू में रखा। इसके पश्चात टीम द्वारा यह प्रदर्शित किया गया कि आपातकालीन परिस्थिति में टापू में फंसे लोगों को किस प्रकार सुरक्षित निकाला जा सकता है। रेस्क्यू दल ने मोटरबोट, लाइफ जैकेट एवं अन्य बचाव उपकरणों की सहायता से टापू में फंसे लोगों को एक-एक कर मुख्य तट पर सुरक्षित रूप से वापस लाया। इस प्रक्रिया में टीम की सतर्कता, समन्वय और दक्षता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई, जिससे यह संदेश गया कि वास्तविक बाढ़ आपदा की स्थिति में भी जिले की तैयारियां पूरी तरह से सक्षम हैं। इसके पश्चात मॉकड्रिल में एक परिदृश्य दिखाया गया, जिसमें कुछ लोग बेहोश हो गए थे। रेस्क्यू टीम ने उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर प्राथमिक चिकित्सा के लिए तत्परता से निकटतम एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इस दौरान यह भी प्रदर्शित किया गया कि किसी व्यक्ति की सांसें बंद हो जाएं या वह बेहोश हो जाए, तो उसे किस तरह से सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) देकर उसकी जान बचाई जा सकती है।

सीपीआर का लाइव डेमो, अधिकारियों ने लिया व्यावहारिक अनुभव-मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने सीपीआर की तकनीक का लाइव डेमो देकर दिखाया कि आपात स्थिति में यह तकनीक कितनी उपयोगी हो सकती है। इस डेमो में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और स्वयं सीपीआर करके देखा कि संकट के समय कैसे एक आम व्यक्ति भी किसी की जान बचा सकता है। मॉकड्रिल के दौरान यह भी बताया गया कि बाढ़ के समय घर में उपलब्ध वस्तुएं जैसे गोल बर्तन, ड्रम, मटका, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब इत्यादि का उपयोग करके अस्थायी राफ्ट या फ्लोटेशन डिवाइस बनाए जा सकते हैं। पानी की एक लीटर बोतल को एयरटाइट कर लाइफ जैकेट के रूप में उपयोग करने का तरीका भी दिखाया गया।

मॉक ड्रिल के दौरान, एसडीआरएफ के प्रशिक्षित अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन के महत्व और त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आपदाओं के समय सही निर्णय लेना और प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ड्रिल में बाढ़ मे फंसे लोगों को निकालने, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव कार्यों की रणनीतियों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया।

मॉक ड्रिल मे दिखाया उपकरणों का प्रदर्शन-बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे मोटरबोट, स्क्यूबा डाइविंग किट, अंडरवाटर कैमरा, लाइफबॉय, चैन-सा, आस्का लाइट, सर्च लाइट और पेलिकन लाइट आदि का भी विस्तृत प्रदर्शन किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिले के पास किसी भी आपदा से निपटने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मॉकड्रिल की सराहना करते हुए कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं अचानक आती हैं और इनसे निपटने के लिए प्रशासनिक सतर्कता, संसाधनों की तत्परता और जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। इस प्रकार की मॉकड्रिल न केवल प्रशासन को आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करती हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी सजग, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाती हैं।उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की घड़ी में हर पल कीमती होता है, और यदि सभी विभाग जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व, आपदा प्रबंधन, नगर सेना सभी संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य करें, तो जान-माल की क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि ग्रामीणों को बाढ़ जैसी परिस्थितियों में घबराने की बजाय शांत और विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए, जिससे रेस्क्यू टीम को सहयोग मिल सके और राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके।

कलेक्टर ने संबंधित

संपादकीय

सोच पर सवाल है गुरुग्राम की त्रासदी

एक विकासमान समाज तभी तक आगे का सफर जारी रख सकता है, जब वह बदलते वक्त के नए मूल्यों को आत्मसात करता है और अपने प्रगतिशील विवेक के साथ बदलाव में संतुलन कायम रखता है। विडंबना यह है कि कई बार समाज की नई पीढ़ी बदलाव में अपनी जगह बनाने के लिए वक्त की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने तंगनजरी या संकीर्णताएं दीवार बन कर खड़ी हो जाती हैं। इस तरह की बाधाएं कई बार इतनी सख्त होती हैं कि उसमें मानवीय संवेदनाओं के लिए भी गुंजाइश नहीं बचती और अपने विवेक से अपना भविष्य बनाने या जीवन-मूल्य चुनने वाले किसी युवा को हिंसा के बल पर रोकना हल मान लिया जाता है।दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जिस तरह एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, उसने एक बार फिर सबको यह सोचने पर मजबूर किया है कि आजादी के सात दशक बाद और विकास के तमाम आधुनिक मूल्यों के बीच समाज आखिर विरोधाभासों की कितनी परतों के बीच जीता है !गौरतलब है कि गुरुग्राम में गुरुवार को राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी रही एक लड़की की उसके पिता ने गुस्से में आकर गोली मार कर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक, इसकी वजह यह थी कि बेटी के एक टेनिस अकादमी चलाने की वजह से पिता को समाज में कुछ लोग अक्सर ताने मारते थे। किसी भी स्थिति में क्या यह इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि इससे खफा होकर कोई पिता अपनी बेटी की जान तक ले ले? संभव है कि पिता ने अपनी बेटी के टेनिस खिलाड़ी बनने और संघर्ष करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के सफर में हरसंभव योगदान दिया होगा। मगर उसके लिए समाज के ताने इतने भारी क्यों हो गए कि वह उसी बेटी का दुश्मन हो गया?आज मौका मिलने पर हर क्षेत्र में लड़कियों ने अपनी क्षमताएं साबित की हैं और यह किसी भी समाज के लिए एक स्वागतयोग्य तस्वीर है। लेकिन यह भी एक तकलीफदेह सच है कि इस समाज का ज्यादातर हिस्सा जिस जड़ता के मानस और पारंपरिक मूल्यों के दायरे में जीता है, उसके बीच एक लड़की का चारदीवारी से बाहर अपनी जगह बनाना, व्यक्तित्व का विकास करना बेहद जद्दोजहद से भरा सफर होता है। इसके बावजूद अगर कोई लड़की अपनी क्षमताओं के बूते आगे बढ़ती है, सार्वजनिक जीवन और गतिविधियों में सक्रिय दिखती है, तो इसे समाज की पितृसत्तात्मक दृष्टि अपने पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ मानती है और उसे रोकने की हर कोशिश की जाती है।गुरुग्राम में अपने पिता के हाथों जान गंवाने वाली बेटी भी दरअसल इन्हीं पितृसत्तात्मक और सामंती मूल्यों की शिकार हुई। एक ओर, टेनिस अकादमी चला कर अपने बूते खड़ा होने और सोशल मीडिया के मंचों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करने वाली लड़की समाज की नजर में सहज स्वीकार्य नहीं हुई, तो दूसरी ओर कुछ लोगों की कुंठाओं से उपजे ताने से पिता इतना आहत हुआ कि उसने अपनी बेटी को ही मार डाला।सवाल है कि पिता का अहं उसकी संवेदना पर भारी क्यों पड़ा! यह एक विचित्र विरोधाभासों के बीच जीते समाज की तस्वीर है, जिसमें लोग आधुनिक तकनीक और संसाधनों की सुख-सुविधाओं को हासिल करने की होड़ में तो लगे हैं।

अमेरिकी नेतृत्व वाले जी-सेवन के मुकाबले ब्रिक्स देशों की जवाबी रणनीति और उसके बारे में सम्बन्धित देशों के द्वारा ना-नुकुर करते रहने से विफ़रे अमेरिकी चिढ़ के अंतरराष्ट्रीय मायने स्पष्ट हैं और ये देर-सबेर अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाले हैं। यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ ब्रेक के बाद फिर से दुनिया में हलचल मचाने लगा है, क्योंकि गत सोमवार को ही उन्होंने अपने मित्र जापान-साउथ कोरिया समेत 14 देशों पर फ्रेश टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

जी7 के मुकाबले ब्रिक्स देशों की जवाबी रणनीति से अमेरिकी चिढ़ के अंतरराष्ट्रीय मायने

(कमलेश पांडे)

सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी रूस की तारीफ करते हैं, कभी भारत से डील चाहते हैं, कभी चीन को पुचकारते हैं, कभी यूरोपीय देशों को हड़काते हैं, कभी पाकिस्तानी प्रेम का इजहार करते हैं तप इसके मायने क्या हैं? शायद फूट डालो और राज करो।

अमेरिकी नेतृत्व वाले जी-सेवन के मुकाबले ब्रिक्स देशों की जवाबी रणनीति और उसके बारे में सम्बन्धित देशों के द्वारा ना-नुकुर करते रहने से विफ़रे अमेरिकी चिढ़ के अंतरराष्ट्रीय मायने स्पष्ट हैं और ये देर-सबेर अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाले हैं। यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ ब्रेक के बाद फिर से दुनिया में हलचल मचाने लगा है, क्योंकि गत सोमवार को ही उन्होंने अपने मित्र जापान-साउथ कोरिया समेत 14 देशों पर फ्रेश टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

वहीं इससे पहले ब्रिक्स पर निशाना साधते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंफ ने कहा है कि जो देश अमेरिकी नीतियों के खिलाफ जाएगा, उस पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि ट्रंप की इस चेतावनी को लेकर ब्रिक्स में शामिल सदस्य देशों ने कड़ी आलोचना की है। इसलिए स्वाभाविक सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, जिसे लेकर ब्रिक्स देश ट्रंप के टारगेट पर हैं और इन अतिरिक्त टैरिफ का इन देशों पर क्या असर होगा, जिसमें उसका कथित मित्र भारत भी शामिल है?

उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके संस्थापक सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। दरअसल, इसका नाम भी इन्हीं पांच देशों के पहले अक्षर को लेकर बनाया गया है। ब्रिक्स का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में आर्थिक सहयोग, विकास और वैश्विक संतुलन बढ़ाना है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई और 1 जनवरी 2024 को ईरान, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिय और संयुक्त अरब अमीरात को भी संगठन में शामिल किया गया था। वैसे तो सऊदी अरब भी इसमें आमंत्रित राष्ट्र के रूप में ग्रुप की गतिविधियों में भाग लेता है, हालांकि अभी तक वह आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ है। शायद अपनी अमेरिकी करीबियों के चलते !

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 2 अप्रैल को ही दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। हालांकि, बाद में इसे 90 दिन के लिए रोक दिया था। इस छूट की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म होने वाली थी, लिहाजा इसे 1 अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया है। वहीं, इससे पहले सोमवार 7 जुलाई को ही ट्रंप ने अपना टैरिफ बम फोड़ना शुरू कर दिया और जापान-साउथ कोरिया के अलावा म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बोस्निया, बांग्लादेश, सर्बिया, कंबोडिया और थाईलैंड पर 25 फीसदी से 40 फीसदी तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ब्रिक्स देशों के लिए एक चेतावनी भी जारी की।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंफ ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा है कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी-अमेरिकन पॉलिसी का समर्थन करेंगे, उन पर 10 फीसदी का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा और अमेरिका की इस नीति में किसी भी तरह की कोई छूट की गुंजाइश नहीं है। इशारा स्पष्ट इशारा भारत की ओर था। यहां बता दें कि ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 6-7 जुलाई को संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक घोषणापत्र में यूएस टैरिफ की आलोचना की गई थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

इसलिए सवाल दर सवाल उभरता है कि आखिर क्या टैरिफ की आलोचना ही एकमात्र कारण है, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंफ ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं, या इसके पीछे और भी कुछ ठोस वजह हैं। यदि ऐसा है तो क्या क्या है, यह जानना हर किसी के लिए जरूरी है। पहली बात तो ये कि इस साल अमेरिकी करेंसी डॉलर में आई तगड़ी गिरावट और बीते कुछ समय में यूएस इकोनॉमी में सुस्ती के कारण ट्रंप को ऐसा लगता है कि हर कोई अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। वहीं, दूसरा बड़ा कारण दुनिया के तमाम बड़े देशों द्वारा डॉलर के उपयोग को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना भी इसके पीछे की वजह समझा जा सकता है।

इस बात का एक बड़ा उदाहरण देखें, तो स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल और आर्थिक रूप से मजबूत रूस और चीन आपस में अपनी करेंसी में ही ट्रेड करते रहे हैं। यही नहीं 2022 में तो रूस ने ब्रिक्स देशों के लिए एक इंटरनेशनल करेंसी का प्रस्ताव भी दिया था। जिससे अमेरिका का चिढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि डॉलर पर बड़े देशों की निर्भरता कम होना अमेरिका के प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जिसको लेकर ट्रंप की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं, जब से अमेरिका ने ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना हथियार बनाया है और ईरान (2012 में) के अलावा रूस (2022 में) को विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी से बाहर रखा गया है, तभी से दुनिया भर के देशों ने अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है।

सच कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को ऐसे ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ब्रिक्स अब वैश्विक आबादी का 45 प्रतिशत हिस्सा है और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में 35 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। अब अगर वे वैश्विक व्यापार में इस समूह में शामिल बड़े देशों द्वारा डॉलर के उपयोग को कम किया जाएगा, तो ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वैसे भी डॉलर में इस साल येन-यूरो के मुकाबले 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है और ये बीते दिनों 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था।

वहीं, अमेरिका की एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी के बाद ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में शामिल ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनसियो लूला दा सिल्वा ने सख्त तेवर दिखाए हैं और 10त्न टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब दुनिया बदल चुकी है और हमें कोई सम्राट नहीं चाहिए। उन्होंने ठीक ही कहा कि ब्रिक्स अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के नए तरीके तलाश रहा है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि कुछ बड़े देश/लोग खुद में असहज महसूस कर रहे हैं। वहीं चीन ने भी स्पष्ट कहा है कि ब्रिक्स किसी भी देश के खिलाफ नहीं है।

सनद रहे कि इससे पहले साल 2025 की शुरुआत में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इसमें शामिल देश वैश्विक व्यापार में डॉलर की भूमिका को चुनौती देंगे, तो फिर उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, ताजा चेतावनी सिर्फ 10 फीसदी की है, जो सुकून की बात है। इस बीच एक अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट की मानें, तो इसमें कहा गया है कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन सभी ब्रिक्स देशों पर तत्काल 10त्न टैरिफ लगाने की योजना नहीं बना रहा है, बल्कि अगर कोई भी देश ऐसे कदम उठाता है जिसे वह अमेरिका विरोधी मानता है, तो उसे इस तरह की अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

वहीं, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ट्रंफ की ये एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स के उस घोषणापत्र पर साइन किए हैं, जिसमें अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की गई। इसलिए ये सवाल भी अहम हो जाता है क्योंकि टैरिफ युद्ध के बीच इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर फाइनल मुहर लगना बाकी है। हालांकि, ट्रंप ने सोमवार को 14 देशों पर नए सिरे से टैरिफ का ऐलान करते हुए भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहा है कि हम भारत के साथ सौदा करने के करीब हैं। भारत के लिए यह उम्मीद की किरण है।

हालांकि, लोकतंत्र के कथित पहरूए और जनद्रोही पूंजीवाद के कट्टर समर्थक अमेरिका को यदि समझना हो तो उसकी उन नीतियों पर गौर करना लाजिमी है, जिसके बल पर वह पूरी दुनिया को हांकता रहता है। कभी तकनीकी क्रांति और कभी आर्थिक लाभ हेतु डॉलर डिप्लोमेसी का सहारा लेने वाला अमेरिका दुनिया भर में पहले झगड़ा लगाने और फिर पंचायती करके लाभ कमाने का आदी रहा है। इसलिए उसकी नीतियों को वक्त वक्त पर अंतरराष्ट्रीय चुनौती भी मिलती रही हैं। भूमंडलीकरण और खुली अर्थव्यवस्था का उन्नायक कब और कैसे मानवता विरोधी खलनायक बन गया, जनशोध का विषय है।

जानकार बताते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन यूरोपीय, एशियाई, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई, दक्षिण अमेरिकी देशों का असरदार सरदार समझा जाता है, जो दुनिया को दर्द बांटकर उसके कारोबारी सफलता हासिल करने के यत्न दर यत्न का घिनौना समर्थन करते रहते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सोवियत संघ (मौजूदा रूस के पड़ोसी देशों का संघ गणराज्य) को चुनौती देकर हथियारों, ड्रग्स सिंडिकेट और कारोबारी सिंडिकेट की आड़ में मानवता को तबाह करने का आरोपी अमेरिका, जब 21वीं के पूर्वार्द्ध में चीन से अनर्गल प्रतिस्पर्धा करता हुआ दिखाई दिया, तो लोगों के मन में सवाल उपजा की, आखिर रूस और भारत के खिलाफ तथा पाकिस्तान के समर्थन हेतु अमेरिका ने जिस चीन में औद्योगिक विकास की रफ्तार दी, आखिर अब वह उसी चीन को अपना कारोबारी दुश्मन क्यों बना बैठा है?

उससे भी बड़ा सवाल यह कि एकमात्र यहूदी देश इजरायल विरोधी इस्लामिक देशों को आपस में लड़वाकर और आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री बनाकर उन्हें बर्बाद करने वाला अमेरिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब इतना लाचार क्यों है? क्या चीन-रूस-उत्तरकोरिया-ईरान की मिलीभगत से उसकी वैश्विक दुनियादारी जनित थानेदारी खतरे में है? क्या अमेरिका-यूरोप विरोधी इस्लामिक देश भी चीन-रूस के नेतृत्व में गोलबंद होकर अमेरिका को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? क्या आतंकवाद विरोधी रुख पर अमेरिका के साथ खड़ा हुआ भारत अब उसके पुराने पाकिस्तान-बंगलादेश प्रेम की घरवापसी होते ही उससे छिटकने को तैयार बैठा है?

सवाल है कि क्या इजरायल, भारत, रूस, जापान, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और ओआईसी से जुड़े 56 कट्टर मुस्लिम देशों के शह-मात से अमेरिका परेशान महसूस करता है? इजरायल-अरब युद्ध उसके गले की हड्डी बन चुकी है या कारोबारी लाभ के नए नए मौके सृजित कर रही है। दुनिया के कई मजबूत देशों को मजबूर बनाए रखने के लिए उसके पड़ोसियों को भड़काए रखने की अमेरिकी रणनीति है, वह बेहद घातक है। इससे मानवता शर्मशार है।

सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अमल करे चुनाव आयोग- अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी हो कड़ी कार्रवाई

(संतोष कुमार पाठक)

दरअसल, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग का काम ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल कर,उन्हें वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट से जीवित मतदाताओं का नाम हटाना नहीं है।

बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान- स्ढ्ढक्र के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लंबी सुनवाई करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए जरूरी मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करे। देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से कई अहम मुद्दों पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक नहीं लगाई है। यानी चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया यह विशेष अभियान चलता रहेगा। लेकिन अदालत ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर बिहार के आम मतदाताओं की मुश्किलों को भी आसान करने का प्रयास किया है। इससे पूरी प्रक्रिया आसान होगी और वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह की आशंकाएं पैदा हो रही है, उसे भी कम करने में मदद मिलेगी।

दरअसल, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग का काम ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल कर, उन्हें वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट से जीवित मतदाताओं का नाम हटाना नहीं है। चुनाव आयोग किसी भी मतदाता से उसका मताधिकार कतई नहीं छीन सकता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, बिहार सहित पूरे देश में आधार कार्ड को जिस तरह से बाकी सभी कार्डों, बैंक खातों और सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, उसके बाद आधार कार्ड को पूरी तरह से खारिज करने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। बिहार में कई जिलों में इस अभियान के तहत आधार कार्ड को स्वीकार किया जा रहा था और कई जिलों में नहीं किया जा रहा था, जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में यह बहुत जरूरी माना जा रहा था कि चुनाव आयोग कोई बीच का रास्ता निकाले।

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एफआईआर पर रोक नहीं लगाई हो लेकिन टाइमिंग को लेकर जो सवाल पूछे हैं, उससे चुनाव आयोग की इस पूरी कवायद पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और चुनाव आयोग के इस अभियान को लेकर सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। हालांकि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने साफ-साफ कहा कि वे संवैधानिक संस्था को वह करने से नहीं रोक सकते जो उसे करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं याचिकाकर्ताओं को उसके एक सप्ताह बाद जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

यह मामला केवल बिहार तक ही सीमित रहने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में मतदाता सूची की समीक्षा कैसे होगी, यह बिहार के मॉडल पर निर्भर करेगा इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।

हालांकि यह भी एक कड़वा सच है कि बिहार सहित देश के कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों की भरमार हो गई है। भारत 70 के दशक से ही बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों से त्रस्त रहा है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान म्यामांर से भी रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ देश में बढ़ती जा रही है। देश के कई जिलों में इन अवैध घुसपैठियों की वजह से हालात काफी भयावह हो गए हैं,इसे नकारा नहीं जा सकता है। बिहार के भी कई जिले, अवैध घुसपैठियों से भरे पड़े हैं, इस सच्चाई को भी खारिज नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि बिहार के सीमांचल इलाकों में अवैध घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार का हर जिला बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से पीड़ित है। बिहार के मिथिलांचल इलाके में भी अवैध घुसपैठियों की संख्या खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन इस समस्या का समाधान कर पाना चुनाव आयोग के वश में नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाना होगा। एक तरफ सीमा से होने वाली घुसपैठ को हर हाल में रोकना होगा, दूसरी तरफ सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक ढांचे को भ्रष्टाचार मुक्त और चुस्त-दुरुस्त बनाना होगा। इसके साथ ही देश में घुस चुके घुसपैठियों को देश से हर कीमत पर बाहर भगाने के लिए भी एक व्यापक अभियान चलाना होगा। यह समय की मांग है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए जल्द से जल्द इस तरह का अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए। लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

घटने लगा जल तो, मछलियों में हलचल

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के एक दिन पहले संवैधानिक संस्था के विरुद्ध चक्का जाम की गलत परंपरा लोकतांत्रिक मान्यताओं के साथ कितना मेल खाती है. महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी लगातार विवाद खड़े कर रहे हैं. यहां तक कि, कांग्रेस की ओर से हाईकोर्ट में भी मामला ले जाया गया था लेकिन उनके आरोप टिक नहीं पाए. बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे जारी रखने पर अपनी सहमति दी है. मामले में सुनवाई चलती रहेगी. चुनाव आयोग जब अपनी प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूरी करने पर अडिग है, हर पात्र मतदाता को उसमें शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, गैर भारतीय किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए आयोग सुनिश्चित कर रहा है तो फिर किसी भी राजनीतिक दल के विरोध का कारण समझ नहीं आता?

(सरयूसुत मिश्रा)

राजनीति के थानेदार राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर वोट की चोरी का आरोप लगा रहे हैं. बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ़ चक्का जाम आंदोलन में महाराष्ट्र में वोट की चोरी का उदाहरण दिया.. !!

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के एक दिन पहले संवैधानिक संस्था के विरुद्ध चक्का जाम की गलत परंपरा लोकतांत्रिक मान्यताओं के साथ कितना मेल खाती है. महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी लगातार विवाद खड़े कर रहे हैं. यहां तक कि, कांग्रेस की ओर से हाईकोर्ट में भी मामला ले जाया गया था लेकिन उनके आरोप टिक नहीं पाए.

बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे जारी रखने पर अपनी सहमति दी है. मामले में सुनवाई चलती रहेगी. चुनाव आयोग जब अपनी प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूरी करने पर अडिग है, हर पात्र मतदाता को उसमें शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, गैर भारतीय किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए आयोग सुनिश्चित कर रहा है तो फिर किसी भी राजनीतिक दल के विरोध का कारण समझ नहीं आता?

सुप्रीम कोर्ट में केवल बिहार के लिए याचिकाएं नहीं लगाई गई है बल्कि बंगाल और दूसरे राज्यों के भी याचिकाकर्ता इसके खिलाफ गए हैं. जहां अभी प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, वह इस आशंका पर कि, उनके राज्य में भी यह होगा, इसलिए इस प्रक्रिया को पहले से ही रुकवा देना बेहतर है. मतदाता सूची पुनरीक्षण चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के सहयोग से ही करता है।

निर्धारित प्रक्रिया में पहले ड्राफ्ट लिस्ट आती है. फिर आपत्तियां आती है. उनका निराकरण होता है. यह पारदर्शी ढंग से राजनीतिक दलों के सामने होता है. फिर भी इसका विरोध समझ के बाहर है. आधार कार्ड को पहचान दस्तावेजों में नहीं शामिल करने के कारण विरोध की बात, तब सही कही जा सकती हैं जबकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऐसी स्थितियां निर्मित होती है कि, बड़ी संख्या में मतदाता छूट जाते हैं।

छूटे हुए मतदाताओं का अलग से इंटेंसिव वेरीफिकेशन आधार कार्ड के साथ अन्य दस्तावेजों और स्थानीय पहचान के साथ की जा सकती है. सारी याचिकाएं राजनीतिक दलों ने लगाई है. किसी मतदाता ने कोई याचिका नहीं लगाई. यह विरोध ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसे एनआरसी और सीएए का विरोध किया गया था. इससे तो ऐसा ही लगता है कि वोट की चोरी अब तक कैसे हो रही थी? और जब उनको हटाने की बात हो रही है तो फिर विरोध की आवाज़ कौन उठा रहा है? पुनरीक्षण होने दिया जाए. जो लोग छूट जाएंगे उनकी बात उसके बाद करना न्यायसंगत होगा. किसी भी पात्र का नाम मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए लेकिन कोई भी अपात्र उसमें होना भी लोकतंत्र के लिए घातक है।

राहुल गांधी जब वोट की चोरी की बात लोकतंत्र में कर ही रहे हैं तो फिर उन्हें उसमें राजनीति की चोरी से भी दो-चार होना पड़ेगा. लोकतंत्र, लोकसेवा के साथ सहयोग से नेतृत्व विकसित होने की प्रक्रिया है. जो नेतृत्व स्वाभविक रूप से विकसित होने के बदले परिवार वादी राजनीति के कारण पैराशूट से उतारे जाते हैं, वह राजनीति लोकतंत्र की चोरी कही जाएगी।

कांग्रेस को ही देखा जाए तो राहुल गांधी जब पार्टी की राजनीति में आए थे, आते ही उन्हें संसद का टिकट मिला. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए. अब तो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी परिवार के कारण ही बनने में सफल हुए हैं. क्या कांग्रेस के भीतर इतनी तेज गति से कोई भी नेता राजनीति में विकास कर पाया है।

कितने राजनेता कांग्रेस में ही दशकों तक आम लोगों के साथ सहयोग और काम करते रहे. ऐसे नेताओं की चप्पलें घिस गईं लेकिन उन्हें पार्षद का भी चुनाव लड़ने का पार्टी में मौका नहीं मिल पाया. राहुल गांधी ऐसे नेता है, जिन्हें बिना किसी राजनीतिक अनुभव और संघर्ष के सब कुछ केवल इसलिए मिल गया कि, वह गांधी परिवार से आते हैं? यह तो लोकतंत्र की बुनियाद के खिलाफ है।

केवल राहुल गांधी नहीं है. जिन भी क्षेत्रीय दलों में परिवारवाद की राजनीति है वहां लोकतंत्र की चोरी हो रही है. बिहार में तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार क्या लोकतंत्र के स्वाभाविक संघर्ष के कारण बन पाए हैं? उन्हें इसलिए यह अवसर मिल रहा है क्योंकि वह लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं. यह तो राजनीति में लोकतंत्र की चोरी का ही नमूना है।

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तब उनके परिवार के ही दशकों तक जन सेवा में जुटे लोगों को दरकिनार किया गया था. शायद इसीलिए परिवारवादी राजनीति के जितने भी युवा वर्तमान में सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, उनकी सोच और शैली में लोकतंत्र परिलक्षित नहीं होता. उनके आरोपों में भी लोकतंत्र की बुनियाद दिखाई नहीं पड़ती।

वोटों की चोरी जैसा शब्द लोकतंत्र में तपा तपाया कोई भी परिपक्व नेता नहीं बोल सकता है. यह वही कह सकता है, जिसके बैक ऑफिस में पेडमैन राजनीतिक आइडिया देते हैं. राजनीतिक डायलॉग देते हैं. संविधान की लाल किताब की राजनीति का आईडिया देते हैं. ऐसे युवा नेताओं को वर्तमान लोकतंत्र इसीलिए नहीं सुहाता है, क्योंकि वह तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं।

इन लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि, लोकतंत्र उन्हें कभी सड़कों पर आने के लिए मजबूर करेगा. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गोद में पले बढ़े परिवारवादी राजनेता सही मायने में लोकतंत्र को चुराकर दूसरों के हक को कुचलकर अपने परिवार की ताकत से मुकाम हासिल किया है।

परिपक्व होते लोकतंत्र के फैसले जिनको भी चोरी लगते हैं. जो भी अपने को लोकतंत्र का थानेदार समझते हैं. उन्हें आरोपों की नहीं, जनसेवा की राजनीति से कुछ भी हासिल हो सकता है. देश में परिवारवादी राजनीति कमजोर हो रही है तो इसका मतलब है कि, लोकतंत्र राजनीति की चोरी से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है।

राहुल डायलाग डिलीवरी में अपने को साबित कर सकते हैं लेकिन लोकतंत्र को अपने भविष्य की पहचान है. कभी राजनीति को जहर बताने वाले राहुल गांधी, सत्ता की छटपटाहट में अब बिना प्रमाण के वोट की चोरी तक का आरोप लगाकर लगा रहे हैं. यह तो बिलकुल ऐसा हो रहा है जैसे कि ' घटने लगा जल तो मछलियों में होने लगी हलचल'.

शीर्ष माओवादी नेताओं ने तेलंगाना में किया सरेंडर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार की सख्ती और ऑपरेशन के दबाव में पस्त हुए नक्सली

चार दशकों तक बस्तर में रहे सक्रिय, दोनों पर था लाखों का इनाम

बस्तर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में लम्बे समय से सक्रिय माओवादी संगठन को उस समय बड़ा झटका लगा, जब संगठन के दो शीर्ष माओवादी नेताओं ने तेलंगाना के राचकोंडा पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में संजीव रूफ उर्फ अशोक और उसकी पत्नी दीना उर्फ पार्वती शामिल हैं। दोनों माओवादी नेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और उन पर लाखों रुपये का इनाम घोषित था।

कौन हैं ये दोनों माओवादी नेता?- संजीव रूफ उर्फ अशोकः माओवादी संगठन की दंडकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी और स्टेट कमेटी मेंबर के पद पर था। वह रणनीतिक संचालन और बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। दीना उर्फ पार्वतीः अशोक की पत्नी और स्वयं भी एससीएम व डीकेएसजेडसीएम के पद पर कार्यरत थी। वह महिला कैडर को प्रशिक्षित करने और संगठन की आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाने में प्रमुख भूमिका निभाती थी। दोनों ने करीब 40 वर्षों तक बस्तर क्षेत्र के जंगलों में नक्सली संगठन की गतिविधियों का नेतृत्व किया, जिनमें दर्जनों माओवादी हमले, पुलिस मुठभेड़, ग्रामीण अपहरण, वसूली, और जन अदालत जैसी घटनाएं शामिल हैं।

ऑपरेशन प्रेशर में टूटी कमर- हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार दबावयुक्त कार्रवाई, आधुनिक तकनीक का उपयोग और माओवाद प्रभावित इलाकों में बढ़ती सड़कों और विकास कार्यों ने माओवादियों को कमजोर कर दिया है। नक्सल ऑपरेशन की सफलता और सरकार की पुनर्वास नीति का ही असर है कि अब शीर्ष नेतृत्व भी हथियार डालने को मजबूर हो गया है।

आत्मसमर्पण से संगठन को लगा करारा झटका- इन दोनों शीर्ष माओवादियों के आत्मसमर्पण को सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सली संगठन के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक झटका बताया है। बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में इनका व्यापक नेटवर्क था, जिसके जरिए कई नक्सली हमलों की योजना बनाई जाती थी।

सरकार की नीति ला रही रंग- तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए विशेष पुनर्वास नीति लागू कर रखी है, जिसके तहत उन्हें सुरक्षा, रोजगार, आर्थिक सहायता और सामाजिक पुनर्स्थापन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, ÷सरेंडर करने वाले माओवादियों को सुरक्षित माहौल और नई जिंदगी देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।÷

बस्तर में अब नक्सलियों का हो रहा लगातार आत्मसमर्पण- इससे पहले भी बस्तर क्षेत्र में कई मध्य और निचले स्तर के नक्सली कैडर सरेंडर कर चुके हैं। परंतु यह पहली बार है कि इतने वरिष्ठ पदों पर रहे माओवादी नेताओं ने खुलकर आत्मसमर्पण किया है। आगे क्या?-इस आत्मसमर्पण से जहां एक ओर संगठन के अंदरूनी ढांचे में दरार पड़ी है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां उम्मीद कर रही हैं कि आने वाले दिनों में और भी माओवादी नेता सरेंडर करेंगे। इसके साथ ही बस्तर क्षेत्र को माओवाद मुक्त करने की रणनीति को अब और गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला दंतेवाड़ा प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लंबित एरिस सहित अन्य मुद्दों को लेकर सौंपा ज्ञापन

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला दंतेवाड़ा प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लंबित एरिस सहित अन्य मुद्दों को मोदी जी की गारंटी अनुसार केंद्र के सम्मान 2त्न मंगाई भत्ता देय तिथि से सम्मिलित करने के लिए सभी संगठनो के पदाधिकारी प्रांतीय आवाहन कमल वर्मा के निर्देश के अनुसार 11 सूत्रीय मांग मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को कलेक्टर कुणाल दुदावत के माध्यम से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपे वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नति समय मान वेतनमान क्रमशः 8 वर्ष ,16 वर्ष ,24 वर्ष ,एवं 30 वर्ष, सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू किया जावे सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समय मान वेतनमान स्वीकृत आदेश जारी किया जावे प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निशत लागू करने स्थाई आदेश जारी किया जाए वर्तमान में 10त्न सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्त दी जाए मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नदीकरण दिया जाए प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ हेतु एन,पी,एस खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जावे साथ की पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु नीति निर्धारित की जावे प्रदेश के विभिन्न मांगों में सेटअप पुनरिचित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभाग में सम्मान था लाते हुए सेवानिवृत वायु 65 वर्ष की जावे प्रदेश में कार्यरत कार्यभारी संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारीयो का नियमितीकरण करते नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जाए युक्त मुद्दों का दिनांक 16 जुलाई 2025 तक निर्णय नहीं दिए जाने के पलस रूप प्रथम चरण में 16 जुलाई 2025 ब्लॉक जिला स्तर पर तथा 22 अगस्त 2025 के पूर्व निर्णय नहीं लिए जाने पर 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को एक दिवसी समय अवकाश लेकर सभी जिला एवं विकासखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जावे महोदय जी से अनुरोध है कि मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023में भाजपा के घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादों को लागू किया जावे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संभाग उपाध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला संयोजक अरविंद यादव जी ,पीलाराम सिन्हा जिला सचिव ,नागेश जासवाल प्रवक्ता ,रामलाल नेताम सदस्य, देवेंद्र चापड़ी,, केशव सिंह, राजकुमार कर्मा ,राजेंद्रसिंह ठाकुर न्यायालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष ,अंकित सिंह उपाध्यक्ष जूरी ,राजेश मांडवी ,कपूर चंद पाल दिनेशकर्मा ,विजय मरकाम अन्य समस्त कर्मचारी गण उपस्थित थे।

जिला शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहलः जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित हुई शिक्षा स्थायी समिति की समीक्षा बैठक

दंतेवाड़ा /मूक पत्रिका

जिला पंचायत सभाकक्ष में बीते गुरुवार को शिक्षा स्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के सभापतिअरविंद कुंजाम ने किया । । बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, सदस्य जितेंद्र सोरी, श्रीमती ममता मंडावी, श्रीमती तिलेश्वरी नागेश, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रमेश गावड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला शिक्षा अधिकारी, मिशन समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खंड स्त्रोत समन्वयक तथा अन्य शैक्षणिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में शिक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और आगामी योजनाओं की दिशा तय करना था। बैठक में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति, जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं निर्माण, पोटाकेबिन स्कूलों में चल रहे कार्यों की स्थिति, विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की नामांकन एवं उपस्थिति की समीक्षा, एकल शिक्षक और शिक्षकविहीन स्कूलों की स्थिति, छात्र-छात्राओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था और बालिका आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षा समिति के सभापति ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी संकुल समन्वयक अनिवार्य रूप से अपनी शालाओं में दो कक्षाएं लें तथा उनके कार्यों के आधार पर हर वर्ष दो संकुल समन्वयकों को पुरस्कृत किया जाएगा।

स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का डंका, राष्ट्रपति मुर्मु ने सात निकायों को किया सम्मानित

विधायक अनुज ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री साय व उप मुख्यमंत्री साव को दी बधाई

रायपुर/मूक पत्रिका

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। जिसमे राज्य के तीन शहरों ने अलग-अलग श्रेणियों में टॉप-3 में जगह बनाकर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है जिसमें प्रथम स्थान पर नगर पंचायत बिल्हा को 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और दूसरे स्थान पर बिलासपुर ने तीन लाख से दस लाख जनसंख्या श्रेणी में देश का दूसरा सबसे साफ शहर बनने का गौरव प्राप्त किया वहीं कुम्हारी को 20 से 50 हजार की आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान मिला है। इस अवसर पर धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देशभर में झंडा गाड़ दिया है,छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि जनभागीदारी और प्रशासनिक प्रतिबद्धता से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।यह सम्मान पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात हैं मैं मुख्यमंत्री व अपने कुशल नेतृत्व से नगरीय निकाय के आयाम गढ़ते उप-मुख्यमंत्री (भारसाधक मंत्री-नगरीय प्रशासन विभाग) अरुण साव और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।

रोड पर मवेशियों से हो रही, दुघर्टनाओं को रोकने के लिए मालिकों पर हो कार्यवाही योजनाओं से वंचित - अशोक पाण्डेय

बेमेतरा/देवकर/मूक पत्रिका

श्री राधेकृष्ण गौ सेवा संस्था गोकुलधाम बोरसी बेरला अध्यक्ष अशोक पाण्डेय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दिए सुझाव.प्रदेश के हर गांव में रोड के किनारे एवं हाईवे रोड में मवेशियों का जमाव रोज देखा जाता है,जिस कारण लगभग हर दिन दुघर्टना होती है।जिसको लेकर श्री राधेकृष्ण गौ सेवा संस्था गोकुलधाम बोरसी बेरला के अध्यक्ष अशोक पाण्डेय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वस्तु स्थिति बताते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि रोड पर व किनारे मवेशियों का जमाव रोज देखा जाता है,जिस कारण लगभग हर दिन दुघर्टना होती है। जिसमें निर्दोष राहगीरों के साथ -साथ मवेशियों की भी मृत्यु हो रही है। जिसमें गौ माता भी शामिल हैं,जो चिंता का विषय है। इसको रोकने का एक ही उपाय हो सकता है। क्यों न मवेशी के मालिकों को चिन्हित कर उनके ऊपर से सक्त कार्यवाही किया जाये और जहां तक हो सके तो सरकार की सभी योजनाओं से वंचित किया जाए ,चाहे मुफ्त राशन क्यों न हो, तभी इस तरह की प्रतिदिन होने वाली दुघर्टनाओं को रोका जा सकता। अतः मेरे इस अनुरोध पर जरूर विचार किया जाये।

14 लीटर अवैध कच्ची महुवा शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार थाना मुलमुला पुलिस की कार्यवाही

जांजगीर चांपा /मूक पत्रिका

आरोपी ईतवारी घृतलहरे उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम नरियरा थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा, के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर चांपा द्वारा लगातार कार्यवाही की की जा रही है। इसी क्रम में थाना मुलमुला पुलिस द्वारा आरोपी ईतवारी घृतलहरे निवासी ग्राम नरियरा को 14 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 2800/? के साथ पकड़ा जिसके विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत् कार्यवाही किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका।

बालक आश्रम हितामेटा बना भ्रष्टाचार का अड्डाः तुलिका कर्मा

आश्रम में ना तो बिस्तर और ना ही शौच के लिए बाथरूम

- अधीक्षक की मनमानी से बच्चों को नहीं मिल रहा मीनू के अनुसार भोजन और ना ही मच्छरदानी, कागजों में आश्रम पूरी तरह ठीक वहीं धरातल में व्यवस्था अत्यंत दयनीय

दंतेवाड़ा /मूक पत्रिका

आदिवासी बच्चों के नाम से आने फंड का दुरूपयोग अगर आपको देखना है तो एक बार बारसूर के हितामेटा स्थित बालक आश्रम देख लिजिए। इस आश्रम में बच्चों के लिए ना तो ठीक से सोने के लिए बिस्तर है और ना ही शौच के लिए बाथरूम। वहीं अगर आप कागजों में देखगें तो आपको पूरी व्यवस्था एकदम ठीक-ठाक दिखेगी। दरअसल कुछ दिन पहले जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने हितामेटा बालक आश्रम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आश्रम में व्याप्त समस्याओं को देख तुलिका कर्मा ने अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। जानकारी देते हुए तुलिका कर्मा ने बताया कि बालक आश्रम हितामेटा में बच्चों के सोने के लिए बिस्तर पूरी तरह टूटा-फुटा है। शौच के लिए बाथरूम नहीं है वहीं मच्छर दानी तक अधीक्षक के तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया है। बच्चों ने तुलिका को बताया कि मीनू अनुसार भोजन भी नहीं मिलता, हर दिन सिर्फ दाल-चांवल खिलाया जाता है। तुलिका ने कहा कि कागजों में आश्रम पूरी तरफ सही पर धरातल पर इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। कुछ दिनों पहले योगा मेट की खरीदी की गई थी। लगभग 300 नग योगा मेट की खरीदी कागजों में दर्ज है पर आश्रम में सिर्फ 3 योगा मेट मिले वो भी काफी पुराने हो चुके हैं। विभाग से बजट दिया जा रहा है पर अधीक्षक द्वारा उसे बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खर्च किया जा रहा है। तुलिका ने बताया कि यही है भाजपा सरकार में विष्णु देव का सुशासन, जहां बच्चों को आश्रम में पेट भर खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। रजिस्टर में दर्ज है किबच्चों के लिए जूते आए हैं पर उन्हें दिया नहीं गया है। बताया जाता है कि आदिवासी बच्चों का हक मार अधीक्षक ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है।

माईजी की नगरी में होगा तुलसी जयंती का भव्य आयोजन प्रांत स्तरीय तुलसी जयंती महोत्सव की रूपरेखा तय हुई

श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष ने दंतेवाड़ा में ली बैठक

दंतेवाड़ा /मूक पत्रिका

महान ग्रंथ श्रीरामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जयंती इस वर्ष 31 जुलाई को मनाई जाएगी। इस मौके पर दंडकारण्य यानी बस्तर में आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा के मेंडका डोबरा मंच पर राज्य स्तरीय तुलसी जयंती महोत्सव का आयोजन होगा। श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ द्वारा यह महोत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। भव्यता, दिव्यता और उल्लास के वातावरण में यह आयोजन होगा। इसकी व्यापक तैयारी के लिए प्रतिष्ठान के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश देशमुख व उनकी टीम ने दंतेवाड़ा स्थित गायत्री मन्दिर में जिला इकाई की बैठक ली। प्रदेश कोषाध्यक्ष छगन हृदय राम सोरी, गुलेश्वर बघेल, राजेश नेताम, मोतीलाल राठौर, आयोजन समिति के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष खिम्मन सिन्हा, उपाध्यक्ष गोपाल सिन्हा , सचिव परीक्षित मंडावी, नीलम ठाकुर, नरेंद्र कुमार साहू, शैलेंद्र ठाकुर, संरक्षक संतोष चौहान, विजेंद्र नाथ जिया सहित मानसप्रेमी सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। आयोजन को भव्य बनाने प्रदेश अध्यक्ष जगदीश देशमुख, जिलाध्यक्ष खिम्मन सिन्हा, गिरधर गोस्वामी ने अपने विचार रखे।व्यवस्थित होगा आयोजन-आयोजन को सुचारू व समयबद्ध तरीके से संपादित करने, शोभायात्रा से लेकर मंच व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक, बैठक , भोजन, पेयजल, आवास, स्वागत मानस मंडलियों, मंच संचालन, कार्यक्रम में अतिथियों के चयन सहित अन्य विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।

विधायक ने जताई प्रसन्नता-प्रतिष्ठान के प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजन समिति के प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय विधायक चैतराम अटामी से मुलाकात कर कार्यक्रम आयोजन के विषय में विस्तृत जानकारी दी। विधायक अटामी ने तुलसी मानस प्रतिष्ठान के इस सांस्कृतिक जागरण के आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस आयोजन में वे तन मन और धन से सहयोग करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश देशमुख ने प्रतिष्ठान के कार्यों और उद्देश्यों को रेखांकित किया।

कार्यशाला में किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, योजनाओं एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी *कार्यक्रमों की विस्तार से दी जानकारी

जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन

जांजगीर चांपा /मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन बीते गुरुवार को ऑडिटोरियम जांजगीर में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि नवाचार, नवीनतम कृषि तकनीकों, योजनाओं एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी कार्यक्रमों की जानकारी देना था। कार्यशाला में फसल चक्र, ऑयल पाम खेती, दलहन-तिलहन, बागवानी, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, कुकुट पालन, पशुपालन, धान के बदले अन्य लाभकारी फसल, कीट प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण कृषि विषयों पर किसानों को जानकारी दी गई। कार्यशाला में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और स्थायी खेती के तरीकों से अवगत कराया गया, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकें। कार्यशाला में कलेक्टर जन्मेजय महोबे सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में कृषक शामिल हुए। कलेक्टर ने कहा कि जांजगीर-चांपा जिला किसानों की मेहनत और समर्पण के कारण एक कृषि प्रधान जिला के रूप में पहचाना जाता है। जिले की लगभग 89 प्रतिशत भूमि सिंचित है, जो कृषि के लिए बेहद अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। कलेक्टर ने कहा कि कार्यशाला किसानों की आय बढ़ाने, उनकी शंकाओं का समाधान करने, शासन की योजनाओं की जानकारी देने और किसानो से सीधी चर्चा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। उन्होंने उन्होंने कहा कि जिले के कुछ किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ लाभकारी फसलों, उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन जैसे क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले के अन्य किसानों को इसने प्रेरणा लेकर नवीनतम कृषि तकनीको व नवाचारो का उपयोग कर अधिक आय अर्जित करने किसानों से अपील की। कलेक्टर ने ब्लाक एवं कलस्टर स्तर पर कृषक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन करने एवं एग्रीस्टेक में किसानों का पंजीयन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कृषक पंजीयन कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिससे पारदर्शिता बढेगी और शासकीय योजनाओं का लाभ किसानों तक सीधे पहुंच सकेगा। साथ ही उन्होंने रबी में अन्य अधिक लाभदायक फसल लेने कृषकों को प्रेरित किया। साथ ही कार्यशाला में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा बताई गई आधुनिक तकनीकों व नवाचारों को अपनाकर कृषि को और अधिक समृद्ध बनाएं। कार्यशाला में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं विशेषज्ञों ने भी जानकारी साझा की। किसानों को विभिन्न कृषि संबंधी योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्नत कृषि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई एवं उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। इस दौरान संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से कृषक पंजीयन, जैविक खेती, दलहन एवं तिलहन फसलों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही किसानों की सफलता की कहानी को वीडियों के माध्यम प्रदर्शन भी किया गया। कार्यशाला में जिला पंचायत सदस्य सुश्री आशा साव, श्रीमती उमा राजेन्द्र राठौर, उप संचालक कृषि ललित मोहन भगत, सहायक संचालक उद्यान श्रीमती रंजना माखीजा, सहायक संचालक मत्स्य, कृषि वैज्ञानिक डॉ आशुलता ध्रुव, शशिकांत सूर्यवंशी, डॉ आशीष प्रधान, डॉ राजीव दिक्षित, डॉ रंजीत मोदी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, प्रगतिशील कृषक सहित बड़ी संख्या में कृषक एवं नागरिकजन उपस्थित थे।

ऑयल पाम खेती के बारे दी गई विस्तार से जानकारी - कार्यशाला में सहायक संचालक उद्यानिकी श्रीमती रंजना माखीजा एवं कृषि वैज्ञानिक डॉ राजीव दिक्षित ऑयल पाम की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कलेक्टर श्री महोबे के निर्देशन में जिले में 500 हेक्टेयर में ऑयल पाम की खेती का लक्ष्य रखा गया है। ऑयल पाम अन्य तिलहन फसलों अधिक लाभदायक है एवं कम देखरेख की आवश्यकता होती है। ऑयल पाम का उत्पादन तीसरे वर्ष से प्रारंभ होकर 25 से 30 वर्षो तक होता है। पौधे की उम्र बढने के साथ-साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। एक हेक्टेयर से प्रति वर्ष 15 से 20 टन तक उपज लिया जा सकता है और किसान सालाना ढ़ाई से तीन लाख रुपये तक की आय प्राप्त कर सकते है।

ऑयल पाम के पौधे एक निश्चित दूरी में लगाए जाते है जिससे किसान इन पौधों के बीच अंतर्वर्ती फसल लगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादित फसल की बिक्री हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनुबंधित कंपनियां सीधे खेत से फसल की खरीदी करती है। इसका भुगतान किसानों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाता है।

संक्षिप्त समाचार

ग्राम पंचायत गंजेनार में चलाया गया स्टॉप डायरिया कैंपिंग

मूक पत्रिका/दंतेवाड़ा – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार विभाग द्वारा वर्षाजनित मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु जिले के ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में ग्राम पंचायत गंजेनार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्टॉप डायरिया कैंपिंग के तहत पेयजल परीक्षण, पेयजल स्त्रोतों के समीप स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल के सेवन, पर आधारित रैली निकाली गई। उक्त रैली में महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा डायरिया, के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और साथ में ही पानी का संरक्षण और पानी की परीक्षण के विषय में भी बताया गया।

आम-सूचना

वाके मौजा गुधेली, प.ह.न. 13 रा.नि.मं गोड़गिरी, तहसील भिभौंरी, जिला बेमेतरा छ.ग. स्थित भूमि जिनका ख.न. 1238, 1240/1 रकबा कमशः 0.0900, 0.0400 हे. तथा ख.न. 1263/1 रकबा 0.10 हे. एवं ख.न. 1264/1 का दु. रकबा 0.10 हे. भूमि के संबंध में एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार हेमंत जैन पिता हरीश चंद जैन निवासी 45/77, मिरा दातार के पास समता कॉलोनी रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ.ग.) ने विकेतागण माखन लाल पिता लखन लाल, पांचो बाई पति स्व. बिहारी साहू, मनोहर साहू पिता स्व. बिहारी साहू, सीताराम साहू पिता स्व. बोधन साहू सभी निवासी ग्राम गुधेली तह. भिभौंरी, जिला बेमेतरा छ.ग. के हक एवं स्वामित्व की भूमि वाके मौजा गुधेली, प.ह.न. 13 रा.नि.मं गोड़गिरी, तहसील भिभौंरी, जिला बेमेतरा छ.ग. स्थित भूमि जिनका ख.न. 1238, 1240/1 रकबा कमशः 0.0900, 0.0400 हे. तथा ख.न. 1263/1 रकबा 0.10 हे. एवं ख.न. 1264/1 का टु. रकबा 0.10 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है से खरीदने का मेरे पक्षकार हेमंत जैन पिता हरीश चंद जैन निवासी 45/77, मिरा दातार के पास समता कॉलोनी रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ.ग.) के द्वारा कर लिया गया है तथा पंजीयन कार्यालय में पंजीयन किया जाना शेष है एवं उक्त वर्णित संव्यवहार के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, सोसायटी, बैंक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, निकाय, महाजन अथवा किसी अन्य को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति या उजर या दावा हो तो आम सूचना के प्रकाशन तिथि के 10 दिनों के भीतर मेरे कार्यालय में दस्तावेज सहित प्रत्यक्ष रूप से अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर पावती लेवें। समयावधि के पश्चात किसी भी प्रकार से आपत्ति या उजर मेरे पक्षकार बंधनकारी नहीं होगा तथा इनके समक्ष शून्य एवं अवैध समझी जावेगी तथा मेरे पक्षकार के पक्ष में बयनामा, पंजीयन निष्पादित कर लिया जावेगा। पर

सो सूचना जाने।

स्थान- बेरला
दिनांक: 17.07.2025

दिलीप कुमार साहू
अधिवक्ता
राजस्व न्यायालय बेरला
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
मो.न. 7999057348

सबसे बड़ी उपलब्धि

स्वच्छ सर्वेक्षण-हमर बिलासपुर पूरे देश में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का परिणाम जारी, 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या में बिलासपुर का पूरे देश में 2 रैंक
- नई दिल्ली में बिलासपुर को मिला प्रेसिडेंसियल अवार्ड,राष्ट्रपति के हाथों उप मुख्यमंत्री,महापौर और निगम कमिश्नर ने ग्रहण किया पुरस्कार

बिलासपुर। बिलासपुर ने इतिहास रच दिया है, बिलासपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है,न्यायधानी बिलासपुर पूरे देश में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। यह बिलासपुर में रहने वाले एवं उससे जुड़े लोगों के लिए गर्व का दिन है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा और पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई। जिसमें बिलासपुर शहर ने टॉप 3 में स्थान बनाते हुए 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल किया है। इससे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बिलासपुर को 28 वां रैंक मिला था। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने दूसरा स्थान हासिल करने पर बिलासपुर को सम्मानित किया है,राष्ट्रपति के हाथों उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव,नगर निगम महापौर श्रीमती पूजा विधानी एवं निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया है। देश के 4589 शहर सर्वेक्षण में शामिल हुए थे। 3 लाख से 10 लाख तक के जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र के मीरा भयंदर और तीसरे स्थान जमशेदपुर को मिला है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावा केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एवं केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री श्री तोखन साहू उपस्थित रहे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत इस साल केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित टीम ने चार चरणों में बिलासपुर का दौरा कर सर्वेक्षण किया था। अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया की गई। सबसे पहले केंद्रीय टीम ने शहर की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी,उसके बाद नागरिकों के फीडबैक,फिर अप्रैल 2025 में स्वच्छता लीग और वाटर प्लस तथा मई माह में गार्बेज फ्री सिटी के लिए सर्वे किया गया था। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण की घोषणा के साथ ही निगम कमिश्नर अमित कुमार ने एक अलग टीम गठित कर सर्वेक्षण की तैयारियों में लगा दिया था,जिनके द्वारा साल भर स्वच्छता एवं उससे जुड़े हुए विशेष अभियान चलाए गए। इससे पहले बिलासपुर को गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार का दर्जा और ओडीएफ का तमगा पहले ही हासिल है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में बिलासपुर ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में शीर्ष तीन में अपनी जगह बनाई है पर यह उपलब्धि ऐसे ही हासिल नहीं हुआ है। इस सफलता के पीछे मजबूत इच्छाशक्ति,लगन,योजनाबद्ध तरीके से किए गए प्रयास के साथ ही सशक्त जनभागीदारी और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है।

बस्तर के किसानों के लिए नई शुरुआत: 'मिलेटअप' प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ

मूक पत्रिका/ बस्तर – जिला बस्तर के गिरोला गांव में किसानों की आय में वृद्धि और स्थानीय कृषि उत्पादों को नया बाजार दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। माँ हिंगलाजिन सेवा समिति द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट 'मिलेटअप' के अंतर्गत स्थापित मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट का विधिवत ट्रायल रन पूजा-अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया।

इस कार्यक्रम में मिलेटअप के सी.ई.ओ. अचिंत गुलाटी एवं मार्केटिंग हेड अर्जुन पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। शुभारंभ अवसर पर माँ हिंगलाजिन मंदिर के प्रमुख पुजारी लोकनाथ बघेल, रामचंद नाग, श्रीमती देवकी बघेल, श्रीमती फूलमती सहित फ्रफ्यूरा टेक्नोलॉजीज़ के इंजीनियर श्री करुणाकरण और अन्य गणमान्यजन मौजूद रहे।

स्थानीय किसानों को मिलेगा सीधा लाभ- यह प्रोजेक्ट न केवल क्षेत्रीय किसानों को मोटे अनाज (मिलेट) के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से बेहतर मूल्य दिलाने का कार्य करेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।

'मिलेटअप' देगा बस्तर के उत्पादों को नई पहचान- इस पहल से बस्तर अंचल के मिलेट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान मिलने की संभावनाएं भी प्रबल हुई हैं। साथ ही यह प्लांट स्वास्थ्यवर्धक मिलेट उत्पादों को आधुनिक तकनीक से प्रसंस्कृत कर आम जनता तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाएगा।

यह योजना बस्तर के विकास की दिशा में न केवल एक नवीन प्रयोग है, बल्कि यह क्षेत्रीय समृद्धि और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी बनने जा रही है।

प्रधान पाठक ड्यूटी समय में बेच रहा है एलआईसी का पॉलिसी

शिक्षक सुरेंद्र ठाकुर उपस्थिति पंजी में अपना हाजिरी लगा कर निकल पड़ते हैं ग्राहकों की तलाश में

शिक्षा विभाग से प्राप्त हो रही सैलरी पड़ रही है कम तो अपने धर्म पत्नी के नाम ले लिया है एलआईसी कोड

मूक पत्रिका/ धमतरी – जिले के नगरी विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगनपुर (संकुल घूरावंड) के शा. प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक सुरेंद्र ठाकुर की नियुक्ति प्रधान पाठक के पद पर आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व में हुई थी। सुरेंद्र ठाकुर कुछ वर्षों से सिंगनपुर स्कूल में एकल शिक्षक थे, बहुत दिनों से उनका एल आई सी का कार्य चल रहा था। अपनी पॉलिसी बेचने के चक्कर में वे स्कूल भी नहीं जाते हैं और जाते भी है तो शीघ्र छुट्टी करके बच्चों को घर भेज देते हैं ताकि सुरेंद्र ठाकुर अपना पॉलिसी बेच सकें। चुकीं शिक्षा विभाग निरीक्षण के लिए सिंगनपुर जाते नहीं है, और इसी बात का पूरा फायदा शिक्षक उठा रहा है। सुरेंद्र ठाकुर का कब स्कूल आना हो रहा है कब जाना हो रहा है किसी को पता नहीं। सिंगनपुर का ग्रामीण जहेल नेताम ने बात स्पष्ट की और बताया कि मैं भी उनका ग्राहक हूं मुझे स्कूल में बुलाकर जबरदस्ती बीमा का फॉर्म डलवाया है। उनका एक और ग्राहक मंगिया राम ने भी बताया कि मुझे भी पॉलिसी बेचने की कोशिश की थी सुरेंद्र ठाकुर ने पर मैंने मना कर दिया लेने से। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र ठाकुर की पत्नी के नाम में एल आई सी की एजेंसी है, और एजेंट का कार्य सुरेंद्र ठाकुर स्वयं करते हैं। शाला में अनुपस्थित होने की वजह से ग्रामीण शिकायत लेकर संकुल समन्वयक के पास गए थे, शिकायत के बाद कुछ महीनों तक लगातार उपस्थित रहते थे। इस सत्र में फिर से उनका यही स्थिति बनी हुई है। उपस्थिति पंजी में हाजिरी भी खुद लगाते हैं,उनके द्वारा उपस्थिति पंजी में प्रत्येक दिन का हाजिरी में उपस्थित दर्शाया गया है।

कांगेर घाटी में घायल हिरण की तड़प-तड़प कर हुई मौत, वन सुरक्षा पर उठे सवाल

मूक पत्रिका/ जगदलपुर। बस्तर के कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान (कांगेरघाटी) में वन्यजीव सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पेदावाड़ा चौक के पास आज दोपहर एक तीर से घायल हिरण जंगल से भागता हुआ नेशनल हाईवे 30 तक पहुंच गया, जहां वह तड़पते हुए गिर पड़ा। राहगीरों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही हिरण की मौत हो गई।

घायल हिरण की तड़पती विदाई - प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हिरण के शरीर में तीर गहरे तक धंसा हुआ था, जिससे वह लगातार खून बहने और दर्द से बेहाल था। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे सड़क किनारे हटाया, लेकिन देर हो चुकी थी। घायल अवस्था में हिरण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

शिकारियों के निशाने पर जंगल के मासूम जीव - कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान के एसडीओ कमल तिवारी ने पुष्टि की है कि हिरण पर शिकार की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया।

वन्यजीव संरक्षण पर गंभीर सवाल -इस घटना ने एक बार फिर संवेदनशील वन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। यह चिंताजनक है कि शिकारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब जंगलों से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक उनकी करतूतें पहुंचने लगी हैं।

नाम परिवर्तन

मैं संतराम पिता सूखी राम आयु 36 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी ग्राम कांपा, पोस्ट कन्हेरा, तहसील दाढ़ी, जिला बेमेतरा (छ.ग.) का निवासी हूं जो कि शपथपूर्वक कथन करता हूं कि :-

1/ यह कि मेरा नाम पता उपर दर्शित अनुसार है।

2/ यह कि, मेरे पुत्र के नाम से जारी आधार कार्ड में अंशु चंद्राकर (ANSHU CHANDRAKAR) दर्ज है, जबकि उसके अंकसूची, जन्म प्रमााण पत्र, समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय/अशासकीय व अन्य समस्त दस्तावेजों में उसका नाम यशु चंद्राकर (YASHU CHANDRAKAR) दर्ज है जो उसका सही वास्तविक नाम है। जबकि उसके आधार कार्ड क्रंमाक 5688 7588 5217 में अंशु चंद्राकर (ANSHU CHANDRAKAR) त्रुटिवश दर्ज हो गया है। मैं अब उसका नाम यशु चंद्राकर (YASHU CHANDRAKAR) पिता संतराम रखना चाहता हूँ, जिसके चलते उसके आधार कार्ड, शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय / व अन्य समस्त दस्तवेजों में जहां कही भी उसका नाम अंशु चंद्राकर (ANSHU CHANDRAKAR) दर्ज है के स्थान पर संशोधन कर- यशु चंद्राकर (YASHU CHANDRAKAR) आ. संतराम रखना चाहता हूं एवं उक्त नाम परिवर्तन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित करवाना चाहता हूं।

3/ यह कि उक्त कथन के समर्थन में यह शपथ-पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत है।

शपथकर्ता
संतराम

नाम परिवर्तन

मैं गणेश राम यादव पिता परषोत्तम यादव आयु 37 वर्ष, निवासी ग्राम मकान नं. 33, डबरी पारा, तेंदूभाठा, पोस्ट बाबा मोहतरा, तहसील व जिला बेमेतरा (छ.ग.) का निवासी हूं जो कि शपथपूर्वक कथन करता हूं कि :-

1/यह कि मेरा नाम व पता उपर दर्शित अनुसार है।

2/ यह कि, मेरे पुत्र के नाम से जारी आधार कार्ड में ईषांत यादव (ISHANT YADAV) दर्ज है, जबकि उसके अंकसूची, जन्म प्रमााण पत्र, समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय/अशासकीय व अन्य समस्त दस्तावेजों में उसका नाम ईशान यादव (ISHAN YADAV) पिता गणेश राम यादव दर्ज है जो उसका सही वास्तविक नाम है। जबकि उसके आधार कार्ड क्रंमाक 3793 1573 1044 में ईषांत यादव (ISHANT YADAV) त्रुटिवश दर्ज हो गया है। मैं अब उसका नाम ईशान यादव (ISHAN YADAV) पिता गणेश राम यादव रखना चाहता हूँ, जिसके चलते उसके आधार कार्ड, शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय / व अन्य समस्त दस्तवेजों में जहां कही भी उसका नाम ईषांत यादव (ISHANT YADAV) दर्ज है के स्थान पर संशोधन कर- ईशान यादव (ISHAN YADAV) आ. गणेश राम यादव रखना चाहता हूं एवं उक्त नाम परिवर्तन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित करवाना चाहता हूं।

3/ यह कि उक्त कथन के समर्थन में यह शपथ-पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत है।

शपथकर्ता
गणेशराम

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला जिला बेमेतरा छ.ग.

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सावित्री पाण्डेय पति सत्यनारायाण पाण्डेय निवासी ग्राम भिभौरी तह भिभौरी जिला बेमेतरा छ0ग0 द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम पिरदा तह भिभौरी जिला बेमेतरा छ.ग. में स्थित खसरा नं 633/1 रकबा 0.02 हे भूमि जो की आवेदक के भूमिस्वामी हक में दर्ज है जिसे आवेदक आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन करने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

24/07/25 अत: इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति का संस्था उजर-दावा हो तो दिनांक तक स्वत: अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शाम 5:00 बजे तक दावा आपत्ति पेश कर सकते है। तथा समय पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक. 07/07/202.50 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय के पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मुहर **बेरला जिला-बेमेतरी (छ.ग.)**

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला जिला बेमेतरा छ.ग.

ईश्तहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि द्वारा एतद् आवेदक सवाई लाल पिता कस्तूरचंद निवासी ग्राम सरदा तह बेरला जिला बेमेतरा छ0ग0 द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम सरदा तह बेरला जिला बेमेतरा छ.ग. में स्थित खसरा नं 578/1, 579/3,579/4 रकबा 0.06, 0.04, 0.02हे भूमि जो की आवेदक के भूमिस्वामी हक में दर्ज है जिसे आवेदक व्यवसायिक सह आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन करने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

24/7/2 अत: इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति का संस्था उजर-दावा हो तो दिनांक तक स्वत: अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शाम 5:00 बजे तक दावा आपत्ति पेश कर सकते है। तथा समय पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय के पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मुहर **बेरला जिला-बेमेतरी (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.कें. 202410230300039/ 14/अ-2/ वर्ष 2024-25

एतद सर्वसाधारण ग्राम/नगर कठौतिया तहसील दाढ़ी जिला बेमेतरा को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका त्रमिल चन्द्राकर पिता नाथुराम चन्द्राकर निवासी मखानी खुर्द तहसील कबीरधाम जिला कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा ग्राम / नगर कठौतिया प.ह.नं. 01 तहसील दाढ़ी जिला बेमेतरा में स्थित उनके नाम की भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 142/24 रकबा 0.02 हे. भूमि को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बाबत् आवेदन पत्र, प्रस्तुत किया गया है।

अत: उक्त संबंध में किसी को कोई दावा आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 21.07.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपात्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मुहर **बेमेतरा, जिला बेमेतरा**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

202507230500003
रा.प्र.क. / अ-2 वर्ष 2024-25

आवेदक श्री सतीश कुमार मारकण्डेय, पिता मदन सिंह मारकण्डेय, साकिन ग्राम कुंरा, तहसील नांदघाट, जिला बेमेतरा (छ.ग.) ने ग्राम अमलडीहा, प.ह.नं. 22, तहसील नांदघाट, जिला बेमेतरा स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 532/1 का रकबा 0.09 हेक्टेयर को व्यवसायिक परिवर्तित मद से औद्योगिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अत: उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति पेश करना हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 18/07/2025 तक/पूर्व न्यायालय में पेश कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

आज दिनांक 03/03/07/2025 को को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मुहर **नवागढ़, जिला-बेमेतरा**

न्यायालय तहसीलदार, बेमेतरा के न्यायालय मे मामला क्रमांक: 202506230600046

मामले की श्रेणी:- राजस्व
सन:- 2024-2025
विषय:- ब-121
अमोरा प.ह.न. 00038 [(हे0)]
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार ओमप्रकाश वर्मा,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक ओमप्रकाश पिता कार्तिक जाति कुर्मी निवासी ग्राम अमोरा तहसील व जिला बेमेतरा ने इस न्यायालय के समक्ष अपने दादी मोंगरा बाई पति खेद्ध का सुत्यु पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया है जिनकी सुत्यु दिनांक 02/04/2023 को स्थान ग्राम अमोरा में होना और भूलवश मुत्यु का पंजीयन नहीं करा पाना बताया गया है।

उक्त आवेदन पत्र के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति को दावा/आपत्ति हो तो वे नियत पेशी तारीख 21/07/2025 तक इस न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी दावा/आपत्ति दर्ज करा सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा किसी भी एक प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में इश्तहार का पेपर प्रकाशन हो।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 23/06/2025 को जारी किया जाता है।

मुहर **तहसीलदार**
बेमेतरा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा – बस्तर का हर गांव बनेगा आपका अच्छा गांव

बीजापुर के युवा पंचों से आत्मीय मुलाकात, बोले ङ्क अब कोई नहीं रोक सकता बस्तर का विकास

बीजापुर /मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में बीजापुर जिले से आए 100 युवा प्रतिनिधियों से आत्मीय मुलाकात की। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत राजधानी रायपुर भ्रमण पर पहुंचे इन युवाओं से मुख्यमंत्री ने गहन चर्चा की और उनके अनुभवों को साझा किया।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से मुस्कुराते हुए कहा, ÷बस्तर का हर गांव अब 'आपका अच्छा गांव' बनेगा। बस्तर के विकास को अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां का युवा आत्मविश्वास से भरा है।÷ उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में बस्तर का समग्र विकास सर्वोपरि है।

युवाओं ने मुख्यमंत्री से बातचीत में बताया कि क्षेत्र में पिछले डेढ़ साल में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं–सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँची है और आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं।

इस दौरान बीजापुर जिले के एक युवा पंच ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि वह जूलॉजी विषय से स्नातक है और वर्तमान में अपने गांव में पंच के रूप में कार्यरत है। उसका एक और साथी भी पंच चुना गया है। युवाओं के इस जज़्बे की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ÷बस्तर का नेतृत्व अब वहां के पढ़े-लिखे युवा करेंगे–यह बदलाव का शुभ संकेत है।÷

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवाओं से हँसी-मजाक के अंदाज़ में पूछा, ÷कितने बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं?÷ जैसे ही कई हाथ उठे, मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ÷अब बस्तर के बच्चे भी हाईटेक हो रहे हैं।÷ यह सुनकर परिसर ठहाकों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने इस पर प्रसन्नता जताई कि बस्तर के युवा तकनीक से जुड़ रहे हैं और उनके गांवों में मोबाइल टावर भी लगाए जा रहे हैं।

युवाओं ने बताया कि उन्होंने राजधानी में मुक्तांगन, जंगल सफारी और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि राजधानी में प्राप्त अनुभवों को आत्मसात करें और अपने गांव में बदलाव के वाहक बनें।

ज्ञात हो कि स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बीजापुर जिले के नियद, नेल्लानार सहित अन्य ग्राम पंचायतों से आए युवाओं का दल दो दिवसीय राजधानी भ्रमण पर है। गुरुवार को ये युवा विधानसभा परिसर पहुँचे, जहां उनके स्वागत में विशेष आयोजन किया गया।

इस अवसर पर राज्य के वनमंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण देव, संपत अग्रवाल, ईश्वर साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

मतदाता जागरूकता हेतु कॉलेजों और 'विद्यालयों में आयोजित होंगे विशेष शिविर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने एवं मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने हेतु जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में आज संयुक्त जिला कार्यालय दंतेवाड़ा के भू-तल स्थित शंकनी सभाकक्ष में उप जिला निर्वाचन अधिकारी मूलचंद चोपड़ा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शिविरों के सफल संचालन हेतु सभी शैक्षणिक संस्थानों में स्वीप नोडल अधिकारी एवं कैंपस एंबेसडर की नियुक्ति, शिविरों की तिथि निर्धारित कर उसे निर्वाचन कार्यालय को सूचित करने तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के छात्र-छात्राओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही विद्यार्थियों को मतदान के महत्व की जानकारी देने, मानव श्रृंखला बनाकर जागरूकता अभियान चलाने एवं शिविरों के दौरान वाद-विवाद, निबंध, रंगोली, चित्रकला, नाटक, नुक्कड़ नाटक जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों के आयोजन की बात कही गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकते हैं। आयोजित शिविरों में संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बीएलओ की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। बैठक में महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्वीप नोडल अधिकारी प्रतिनिधि तथा जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

सरहरी में संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास से संपन्न

नवप्रवेशी बच्चों का हुआ पारंपरिक स्वागत, शिक्षा को लेकर अभिभावकों में दिखा उत्साह

सूरजपुर/प्रतापपुर-सरहरी/मूक पत्रिका

विकासखंड प्रतापपुर अंतर्गत संकुल केंद्र सरहरी में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन अत्यंत उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरहरी की सरपंच मिनामती कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं, जबकि शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामशरण कुशवाहा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान करने हेतु मंच पर ग्राम पंचायत सेमरा खुर्द के सरपंच और उपसरपंच, ग्राम पंचायत सरहरी के उपसरपंच, प्रेमचंद कुशवाहा, विजयनारायण कुशवाहा, रुद्र प्रसाद कुशवाहा, अरविंद पटेल, कश्यप जी एवं लक्ष्मण धुर्वे जैसे क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

दीप प्रज्वलन से प्रारंभ, नवप्रवेशी बच्चों का तिलक–मालाओं से स्वागत– कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पूजन के साथ की गई। इसके पश्चात कक्षा 1वीं, 6वीं और 9वीं में प्रवेश लेने वाले नवप्रवेशी विद्यार्थियों का पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर, माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर आत्मीय स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्हें पाठ्यपुस्तकें और गणवेश भी वितरित की गई, जिससे यह अवसर बच्चों और उनके परिजनों के लिए अविस्मरणीय बन गया।

शिक्षकों, पालकों और विद्यार्थियों की रही उत्साहपूर्ण भागीदारी– इस आयोजन में विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती निशा तिवारी, संकुल अंतर्गत सभी प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठकगण, व्याख्याता, शिक्षकगण, अभिभावकगण तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। आयोजन की गरिमा को देखते हुए उपस्थितजन पूरे समय आयोजन से जुड़े रहे और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं से वातावरण को ऊर्जा दी।

संचालन और आभार प्रदर्शन– कार्यक्रम का संचालन चंद्रिका प्रसाद चतुर्वेदी ने प्रभावशाली ढंग से किया। वहीं, सीएसी सरहरी इंद्रबली कुशवाहा ने अंत में आभार प्रदर्शन करते हुए सभी मुख्य अतिथियों, विशिष्ट जनों, अभिभावकों एवं सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

सामाजिक सहभागिता की मिसाल बना यह आयोजन– यह शाला प्रवेश उत्सव न केवल बच्चों के लिए उमंग और उत्साह का अवसर बना, बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों के बीच शिक्षा के महत्व को साझा करने और सामाजिक सहभागिता को सशक्त करने का सशक्त मंच भी सिद्ध हुआ। सभी अतिथियों ने विद्यालय परिवार की प्रयासों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की।

भैयाथान ष्टा्नष्ट में एक्स-रे सेवा ठपः 2018 में लगी मशीन बेकार, गप्पबाज़ रेडियोग्राफर की मनमानी से मरीज बेहाल

सूरजपुर/भैयाथानः/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लाख दावे करे, लेकिन भैयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ष्टा्नष्ट) की हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। यहां 2018 में लगाई गई पोर्टेबल एक्स-रे मशीन लगभग बेकार साबित हो रही है, क्योंकि रेडियोग्राफर की लापरवाही और राजनीतिक संरक्षण के चलते यह सेवा अब लगभग बंद पड़ी है।

छह साल से मशीन, लेकिन सेवा नदारद– भैयाथान ष्टा्नष्ट में पोर्टेबल एक्स-रे मशीन वर्ष 2018 में स्थापित की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को समय पर एक्स-रे जांच उपलब्ध हो सके। लेकिन छह साल बीत जाने के बाद भी इस सुविधा का लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है। मशीन तो है, पर ऑपरेटर की मनमानी के कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा।

हमेशा बंद रहता एक्स–रे रूम, मरीज दर–दर की ठोकरें खाते– स्वास्थ्य केंद्र में स्थित एक्स-रे कक्ष अक्सर ताले में जकड़ा रहता है। मरीज इलाज के लिए आते हैं लेकिन ताला देख मायूस लौट जाते हैं। रेडियोग्राफर राकेश जायसवाल अकसर ऑफिस में क्चरूह्र डॉ. राकेश सिंह के साथ गप्पें मारते दिखते हैं। आरोप है कि उनकी राजनीतिक पहुंच इतनी मजबूत है कि कोई उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता।

सेवा नहीं, सिफारिश और संरक्षण का खेल– सूत्रों के अनुसार, राकेश जायसवाल की ड्यूटी जहां भी लगती है, वहां एक्स-रे सेवा लगभग ठप हो जाती है। मरीजों को मजबूरी में सूरजपुर जिला अस्पताल या महंगे निजी लैब्स जाना पड़ता है, जिससे गरीबों की जेब पर ?300-?400 का अनावश्यक बोझ पड़ता है।

टीबी मरीज हो रहे सबसे ज्यादा प्रभावित– भैयाथान ष्टा्नष्ट में प्रतिदिन बड़ी संख्या में टीबी के मरीज आते हैं, जिनके लिए बलगम जांच के साथ एक्स-रे भी अनिवार्य होता है। लेकिन एक्स-रे न होने से न केवल इलाज में देरी हो रही है, बल्कि संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है।

सरकारी योजनाओं को लग रहा झटका– छत्तीसगढ़ सरकार की जनसेवा से जुड़ी योजनाएं ऐसे गैर-जिम्मेदार कर्मचारियों के कारण दम तोड़ रही हैं। लाखों रुपये की लागत से लाई गई मशीन और करोड़ों के बजट के बावजूद ग्रामीण जनता अब भी उपचार के लिए तरस रही है।

राजनीतिक संरक्षण बना मनमानी की ढाल– सूत्रों की मानें तो राकेश जायसवाल को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के करीबी रिश्तेदारों का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में वह ड्यूटी से गायब रहना, अनुशासनहीनता और मरीजों की उपेक्षा जैसे कृत्य बेरोकटोक कर पा रहे हैं।

प्रशासन की परीक्षाः कार्रवाई होगी या लापरवाही जारी रहेगी?– अब यह देखना होगा कि क्या इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन कोई कठोर कदम उठाएगा या फिर सरकारी सिस्टम इन राजनीतिक संरक्षित कर्मचारियों के आगे फिर एक बार नतमस्तक हो जाएगा?

बयान– विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी राकेश सिंह के द्वारा बताया गया कि पिछले 15 दिनों से एक्सरे मशीन खराब है जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई, इंजीनियरों के आने के बाद पुनः चालू हो जाएगी।

महतारी वंदन योजना ने खोले आत्मनिर्भरता के द्वार

सूरजपुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल बन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। योजना के तहत अब तक 11081.68 करोड़ रुपये की राशि 69.23 लाख से अधिक हितग्राही महिलाओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से अंतरित की जा चुकी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि ,महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता का जरिया नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मानजनक और सशक्त जीवन की ओर बढ़ाने वाला माध्यम है। यह योजना राज्य की महिलाओं के आत्मबल, स्वास्थ्य और समाज में भागीदारी को मजबूत करने का कार्य कर रही है। इस योजना की 17वीं किश्त का वितरण 1 जुलाई 2025 को किया गया, जिसमें 647.66 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य शासन द्वारा दी जाती है।

नारायणपुर जिले के बासिंग गांव की निवासी श्रीमती एतवारिन कुमेटी इस योजना का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने सरकारी सहयोग से मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ठोस कदम उठाया। वर्षों तक मजदूरी कर जीवन बिताने वाली श्रीमती एतवारिन कहती हैं। मुझे अब तक योजना से 17,000 रुपये की सहायता मिली है। इस राशि ने न सिर्फ मेरी आर्थिक स्थिति सुधारी बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अब मैं अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हूं और अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रही हूं।

वह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े का आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि महतारी वंदन योजना हमारे जैसे महिलाओं के लिए वरदान है, जो हमारे जीवन में उम्मीद और बदलाव लेकर आई है।

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलका–अघीना में गिरा विशालकाय वृक्ष, बाल–बाल बचे छात्राएं

सूरजपुर//मूक पत्रिका

सलका - अघीना शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब स्कूल परिसर में स्थित वर्षों पुराना विशालकाय पेड़ अचानक धराशायी होकर विद्यालय की छत पर गिर पड़ा। घटना के समय स्कूल में दर्जनों छात्राएं मौजूद थीं, लेकिन सौभाग्यवश कोई हताहत नहीं हुआ।

विद्यालय की छत पर गिरा यह भारी-भरकम वृक्ष कई वर्षों पुराना बताया जा रहा है, जिसकी जड़ें समय और मौसम के कारण कमजोर हो चुकी थीं। लगातार हो रही बारिश ने स्थिति को और भी खतरनाक बना दिया, और आखिरकार यह विशालकाय वृक्ष विद्यालय भवन पर आ गिरा।

गंभीर लापरवाही, बड़ा हादसा टला- स्थानीय लोगों और छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि पेड़ की हालत पहले से ही जर्जर थी और उसकी छटाई या हटाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण यह संभावित दुर्घटना बनकर सामने आया। यदि यह वृक्ष स्कूल की छुट्टी के समय या छात्रों की कक्षाओं के

दौरान गिरता, तो एक बड़ी त्रासदी से इंकार नहीं किया जा सकता था।

जिम्मेदार कौन?- इस गंभीर लापरवाही को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या स्कूल प्रबंधन को इस खतरे की जानकारी नहीं थी? समय रहते वृक्ष की छंटाई क्यों नहीं की गई? क्या किसी बड़ी घटना का इंतज़ार किया जा रहा था?

इस विषय में विद्यालय के एसएमडीसी अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश दुबे से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा, जिससे जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर और भी सवाल उठने लगे हैं।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग- स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि स्कूल परिसरों में स्थित पुराने व जर्जर वृक्षों की समय-समय पर जांच की जाए और संभावित खतरों को समय रहते दूर किया जाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

एक बड़ी घटना टल गई है, लेकिन अगर प्रशासन और जिम्मेदार अब भी नहीं जागे तो अगली बार यह चूक जानलेवा साबित हो सकती है।

कलेक्टर ने स्कूलों के निरीक्षण के लिए जारी किया आदेश,अधिकारी स्कूल पहुंचकर शिक्षा एवं अध्यापन की गुणवत्ता सहित स्कूल व विद्यार्थियों की समस्या का करेंगे निराकरण

एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार प्रति सप्ताह करेंगे 3 स्कूल और 2 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण

जिला शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों प्रति सप्ताह 10 शासकिय विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश

संकुल प्रभारी प्राचार्य, संकुल शैक्षिक समन्वयक अपने संकुल अंतर्गत आने वाले समस्त विद्यालयों का प्रति सप्ताह करेंगे निरीक्षण

अधिकारियों को समय सीमा की बैठक में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले के शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु उत्कृष्ट जांजगीर अभियान-2 चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जिले में संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्दों के निरीक्षण के लिए एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के जिला व विकासखंड स्तरीय अधिकारी को निरीक्षण करने हेतु आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सप्ताह में कम से कम 03 शासकीय प्राथमिक, मिडिल, हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों एवं 02 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के साथ-साथ स्कूल एवं विद्यार्थियों से संबंधित समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों प्रति सप्ताह 10 शासकिय विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सर्व संकुल प्रभारी प्राचार्य व सर्व संकुल शैक्षिक समन्वयक अपने समस्त संकुल क्षेत्र के समस्त विद्यालयों का प्रति सप्ताह निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रति सप्ताह समय-सीमा की बैठक में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान दैनिक उपस्थिति, कक्षा प्रबंधन, पाठ्यक्रम का पालन, पीटीएम का आयोजन, विनोबा एप्प में प्रविष्टि सहित अन्य गतिविधियों का अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 31 जुलाई तक

कलेक्टर ने परिवार कल्याण प्रचार-प्रसार रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

मुंगेली/मूक पत्रिका

जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा परिवार नियोजन सेवाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के साथ ही लोगों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आज जिला कलेक्टोरेट परिसर से जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के सफलता के लिये प्रचार-प्रसार रथ को हरी झण्डी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के समुचित रूप से पालन-पोषण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के समुचित विकास के लिए परिवार नियोजन आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन अपनाने लोगों को जागरूक करने के लिए पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिससे लोगों में निश्चित रूप से जागरूकता आएगी। परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, यह जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक स्थिरता का आधार है। इस दौरान अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अपर कलेक्टर जी. एल. यादव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक गिरीश कुर्रे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शीला साहा ने बताया कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए प्रचार-प्रसार रथ विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न ग्रामों में पहुँचेगी, जहां लोगों को परिवार नियोजन से संबंधित परामर्श दिया जाएगा। इस दौरान सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवार नियोजन के अस्थाई साधनों की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय, 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल लोरमी और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पथरिया में नसबंदी की सुविधा उपलब्ध है। पुरूष नसबंदी कराने पर 03 हजार रूपए एवं महिला नसबंदी कराने पर 02 हजार रूपए तथा प्रसव पश्चात नसबंदी कराने पर 03 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी और स्वास्थ्यगत समस्या के निराकरण के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल किया जा सकता है।

जांजगीर चांपा में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्यवाही: पटवारी 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

पटवारी बालमुकुंद राठौर को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा

जांजगीर चांपा/मूक पत्रिका

जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफएक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुटपुरा और धाराशिव गांव के प्रभारी पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

आरोपी पटवारी बालमुकुंद राठौर, एक किसान से खाता दुरुस्ती के एवज में 20 हजार रुपए की मांग कर रहा था। बीते गुरुवार दोपहर जांजगीर जिले के पुटपुरा गांव स्थित पटवारी कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापा मारा और पटवारी बालमुकुंद राठौर को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। शिकायतकर्ता सत्येंद्र कुमार राठौर, जो कि जांजगीर की पुरानी बस्ती का निवासी है, ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि उसकी पुश्तैनी 4 एकड़ से अधिक जमीन पुटपुरा गांव में स्थित है। पिछले डेढ़ साल से वह जमीन के खाता सुधार के लिए आवेदन दे रहा था, लेकिन पटवारी उसे लगातार टालता रहा और आखिरकार 20 हजार रुपए की मांग की। शिकायत की पुष्टि के बाद ए सी बी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। सत्येंद्र ने आज दोपहर 12 बजे पटवारी कार्यालय पहुंचकर कैमिकल लगे नोटों के साथ पैसे सौंपे, जिसके तुरंत बाद टीम ने छापा मारा और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। ए सी बी थाना प्रभारी योगेश कुमार राठौर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बरामद नोटों को जब्त कर विधिवत जांच जारी है।

जनसंख्या वृद्धि की गति को कम करना आर्थिक विकास,स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी -डॉ मनीष बंजारा

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुर में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा आयोजित

मुंगेली/मूक पत्रिका

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शीला साहा व जिला कार्यक्रम प्रबंधक गिरीश कुर्रे के निर्देशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुर में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया गया । इसका आयोजन 11 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 2025 का स्लोगन ''मॉ बनने की उम्र वही, जब तन और मन की तैयारी सही '' रखा गया है। डॉ मनीष बंजारा ने बताया कि जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के दौरान जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाना एवं परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों के संबंध में प्रोत्साहित किया गया उन्होंने कहा कि संतुलित आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या सस्थिरीकरण आवश्यक है. जनसंख्या स्तरीकरण का तात्पर्य है जनसंख्या वृद्धि दर को इस स्तर पर जाना, जहां जन्म दर और मृत्यु दर के बीच संतुलन बना रहे.जनसंख्या स्तरीकरण भारत के सतत विकास, संसाधनों के संरक्षण और सामाजिक स्थिरता के लिए अत्यंत जरूरी है।आगे कहा की देश की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि की गति को नियंत्रित करना, संसाधनों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना एवं नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु जागरूकता शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अति आवश्यक है, परिवार नियोजन के उपायों जैसे गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता और जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों तक फैलाना है। जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को सफल बनाएं। यह न केवल देश के भविष्य के लिए जरूरी है, बल्कि हर परिवार के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी हितों के लिए भी आवश्यक है। परिवार नियोजन विशेष रूप से जन्मों के बीच अंतराल बनाए रखने से, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद करता है। परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक विधियों का उपयोग करके, अनचाहे गर्भधारण को रोकने में मदद करता है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। परिवार नियोजन व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, और सामाजिक कल्याण में योगदान देता है। अंत में आबादी पर करो नियंत्रण तरक्की को दो आमंत्रण के नारे भी लगाए।इस अवसर पर सीमा पहारी, मिथलेश राठौर,सुनीता मिरि, मोनिका, किशोर, दिवाकर जलेश्वरी सुधा त्रिवेणी उपस्थित रहे।

माओवादियों की साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने दो IED बरामद कर किया नष्ट

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले में माओवादियों द्वारा सुरक्षाबलों को नुकसान पहुँचाने की एक और नापाक कोशिश को सुरक्षा बलों ने सतर्कता से नाकाम कर दिया। जिले के उसूर क्षेत्र में एरिया डॉमिनेशन और डिमाईनिंग ड्यूटी पर निकली सुरक्षा टीम ने दो ढ्ढश्वष्ठ बरामद किए, जिन्हें मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों की टीम उसूर कैम्प से टेकमेटला की ओर रवाना हुई थी। इसी दौरान कच्चे रास्ते पर माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए दो बीयर बॉटल आईईडी का सुरक्षाबलों ने समय रहते पता लगा लिया। तत्काल बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया, जिसने दोनों विस्फोटकों को निष्क्रिय कर संभावित बड़ी घटना को टाल दिया। सुरक्षा बलों की सतर्कता और तत्परता से एक बार फिर माओवादियों की हिंसात्मक योजना को विफल कर दिया गया है। इलाके में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है।

सरस्वती शिशु मंदिर चांपा में मातृभाषा के महत्व के साथ आधुनिक शिक्षा का समन्वय

जांजगीर चांपा/मूक पत्रिका

÷मां, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं होता÷—इसी विचारधारा को आत्मसात करते हुए स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा के पारंपरिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक और व्यवहारिक विषयों का अनोखा समावेश किया गया है। सशिमं में स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर शिक्षा, संगीत, एवं नैतिक शिक्षा जैसे विषयों को विशेष रूप से पढ़ाया जा रहा है। सशिमं प्रशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को न केवल किताबी ज्ञान देना है, बल्कि उन्हें जीवन के लिए उपयोगी विषयों पर भी गहन समझ देना है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को योग, ध्यान, आध्यात्म, और स्वयं विश्लेषण की विशेष शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। सशिमं में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए गायन, विज्ञान, वाणिज्य, और सांस्कृतिक विषयों की प्रभावी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही, 25 मिनट का संयमित ध्यान एवं योग कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। खास बात यह है कि सशिमं में बच्चों के मनोरंजन और शारीरिक विकास के लिए विशाल खेल सामग्री संग्रह है, और उन्हें खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यह प्रयास मातृभाषा की गरिमा को बनाए रखते हुए विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहा है।

जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने जगदलपुर के विकास कार्यों के लिए 49 करोड़ 42 लाख कराये स्वीकृत-- राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा

जगदलपुर /मूक पत्रिका

मुख्यालय में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने 49 करोड़ 42 लाख शहर विकास के लिए स्वीकृत कराये। विकास कार्यों को महत्वपूर्ण मानने वाले और उन्हें आगे बढ़ाने वाले विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव को विकास पुरुष के रूप मे देखा जा रहा है। शहर के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विकास कार्यों को समर्थन दे रहे हैं। विधायक जगदलपुर ने एमपीएम हॉस्पिटल से एलआईसी ऑफिस रोड सड़क निर्माण के लिए 2 करोड रुपए, धरमपुरा नालंदा परिसर सेंट्रल लाइब्रेरी हेतु 11 करोड़ 42 लाख, दलपत सागर सफाई व सौंदरीकरण के लिए 10 करोड रुपए, मुक्तिधाम से समुद्र चौक से लालबाग आमागुड़ा चौक तक सड़क व अन्य निर्माण कार्य 24 करोड रुपए एवं बोधघाट थाना से कमिश्नर ऑफिस तक बीटी सड़क निर्माण 2 करोड रुपए कुल राशि 49 करोड़ 42 लख रुपए विधायक जगदलपुर की अनुशंसा पर स्वीकृत हुए हैं। राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने कहा नव संकल्प,नव उत्साह और मन में नए विचार के साथ विधायक जगदलपुर शहर विकास को लेकर सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं।जगदलपुर विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और विकास कार्यों को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, जगदलपुर महापौर संजय पांडे, नगर निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन सहित जगदलपुर की समस्त जनता का धन्यवाद जिनके आशीर्वाद व सहयोग से शहर विकास के लिए राशि स्वीकृत हुई।

बिचौलियों को भारी मात्रा में सप्लाई,सेल्समैन कर रहे है एमआरपी से ज्यादा वसूली

शासन की आंखों में धूल झोंकते सरकारी शराब दुकानों में मची लूट

जगदलपुर/मूक पत्रिका

पवन कुमार नाग - मुख्यालय के सरकारी शराब दुकानों में आबकारी विभाग के अधिकारियों और एजेंसी कर्मचारियों की मिलीभगत से बिचौलिए सक्रिय हैं, जो एमआरपी से अधिक दाम पर शराब की खुलेआम बिक्री करवा रहे हैं। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक युवक को बैग में शराब की बोतलें भरकर ले जाते रंगे हाथों पकड़ा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी शराब दुकानों में ग्राहकों को न बिल दिया जा रहा है और न ही एमआरपी का पालन, जिससे आमजन को प्रतिदिन लूटा जा रहा है। नियम के मुताबिक हर बिक्री पर बिल देना अनिवार्य है, लेकिन यहां बिल मांगने पर बहानेबाज़ी और झगड़े की नौबत तक आ जाती है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि चांदनी चौक की दुकान से एक ही युवक को बार-बार शराब की सप्लाई की जा रही है, और यह सब अधिकारियों की जानकारी में हो रहा है। मीडिया में शिकायत और खबर छपने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल यह उठ रहा है कि जब दिन के उजाले में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, तो रात के अंधेरे में कितनी अवैध बिक्री और कालाबाजारी चलती होगी? आबकारी विभाग की चुप्पी भी कई सवालों को जन्म देती है। आम लोगो ने चर्चा में बताया कि स्थानीय प्रशासन को बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिये। शराब दुकानों की सीसीटीवी से निगरानी की जाए।

दुकानों पर एमआरपी का पालन अनिवार्य कराया जाए। ग्राहकों को बिल अनिवार्य रूप से दिया जाए।निष्कर्ष: शराब बिक्री में गड़बड़ी और बिचौलियों की सक्रियता से न केवल शासन को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि समाज में भी गलत संदेश जा रहा है। अगर अब भी कार्रवाई नहीं होती, तो यह स्पष्ट होगा कि प्रशासनिक मिलीभगत से ही यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा स्वामी डीबी कार्प लिमिटेड के लिए प्लाट नम्बर 40/44 इंडस्ट्रियल एरिया बीरगांव रोड, उरला, रायपुर से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।